राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण बुधवार 28 जनवरी 2026 वर्ष-9,अंक-05 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारत और यूरोपीय देशों के लिए मुक्त व्यापार समझौता बड़ा अवसर: प्रधानमंत्री मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि यूरोपीय देशों से भारत की डील को लोग दुनिया में 'मदर ऑफ ऑल डील' कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोमवार को भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुत बड़ा समझौता हुआ है। यह मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने यह बात आज दक्षिण गोवा में आयोजित भारत ऊर्जा सप्ताह (इंडिया एनर्जी वीक-2026) के चौथे संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए कही।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कल ही भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया में लोग इसकी चर्चा 'मदर ऑफ ऑल डील' के रूप में कर रहे हैं। यह समझौता भारत के 140 करोड़ लोगों और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। यह समझौता, दुनिया की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। यह समझौता ग्लोबल जीडीपी के करीब 25 प्रतिशत और ग्लोबल ट्रेड के लगभग एक-तिहाई हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। यह समझौता ट्रेड के साथ-साथ डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी सशक्त करता है।

उन्होंने कहा, भारत ऊर्जा सप्ताह के नए संस्करण में गोवा में दुनिया के करीब 125 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। आप एक एनर्जी सुरक्षित और टिकाऊ भविष्य पर चर्चा करने भारत आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। इंडिया एनर्जी वीक बहुत कम समय में संवाद और कार्य का एक ग्लोबल प्लेटफार्म बन कर उभरा है। आज एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बड़े अवसरों की धरती है। भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत, दुनिया की डिमांड की पूर्ति के लिए भी बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराता है। आज हम, दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप पांच निर्यातकों में से एक हैं। दुनिया के 150 से भी अधिक देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है। भारत की ये क्षमताएं आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसलिए, एनर्जी वीक का यह प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का उपयुक्त स्थान है।

पांच दिवसीय वर्किंग की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 27 जनवरी को कामकाज पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 5-डे वर्किंग यानी सप्ताह में केवल पांच दिन काम करने की अपनी लंबे समय से लंबित मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इस हड़ताल की घोषणा 23 जनवरी को की गई थी, और यदि यह योजना के अनुसार सफल रहती है, तो आम नागरिकों और व्यापारिक लेन-देन पर इसका व्यापक असर पड़ना तय है।

यह हड़ताल इसलिए भी अधिक चिंताजनक है क्योंकि इसके चलते बैंकों में लगातार चार दिनों तक ताले लटके रह सकते हैं। 24 जनवरी को महीने का दूसरा शनिवार था, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय अवकाश के कारण बैंक पहले से ही बंद थे। ऐसे में 27 जनवरी की हड़ताल बैंकिंग सेवाओं के व्यवधान को और अधिक बढ़ा देगी। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अपने ग्राहकों को इस संभावित परेशानी के बारे में पहले ही सचेत कर दिया है। हालांकि, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों के कामकाज पर इस हड़ताल का कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

हड़ताल का नेतृत्व कर रहे नौ प्रमुख यूनियनों के समूह, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने बताया कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई हालिया बैठकें बेनतीजा रही हैं। यूनियनों का कहना है कि सरकार और भारतीय बैंक संघ के बीच मार्च 2024 में हुए वेतन संशोधन समझौते के दौरान सभी शनिवार को अवकाश घोषित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यूनियनों का तर्क है कि वे सप्ताह में दो दिन के अवकाश के बदले सोमवार से शुक्रवार तक रोजाना 40 मिनट अतिरिक्त काम करने के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना है कि जब आरबीआई, एलआईसी, स्टॉक एक्सचेंज और सरकारी कार्यालय पहले से ही पांच-दिवसीय कार्य सप्ताह का पालन कर रहे हैं, तो बैंक कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखना उचित नहीं है। फिलहाल, अपनी मांगों पर अडिग कर्मचारी संघ इस विरोध प्रदर्शन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं।

ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा ने बाहर निकाला

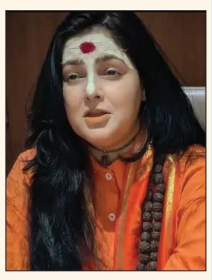

प्रयागराज (एजेंसी)। किन्नर अखाड़ा से महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी को बाहर कर दिया गया है। इसकी पुष्टि अखाड़े की प्रमुख महामंडलेश्वर डॉ. लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने वीडियो जारी कर किया। उन्होंने कहा कि अखाड़े के पदाधिकारी से बैठक करके यह निर्णय लिया है। अब ममता कुलकर्णी से अखाड़े का कोई संबंध नहीं है। वह अखाड़े की अधिकारी या सदस्य नहीं हैं। हमारे अखाड़े में महिला भी हैं, पुरुष भी हैं और किन्नर भी हैं। हम किसी तरह का विवाद नहीं चाहते हैं। मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से बटुक ब्राह्मणों को शिखा पकडक़र पीटा गया, इससे हमारी भी नाराजगी है। 25 जनवरी (रविवार) को ममता कुलकर्णी (यामाई ममता नंद गिरि) ने अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर कहा था कि 10 में से 9 महामंडलेश्वर और तथाकथित शंकराचार्य झूठे हैं और उन्हें शून्य ज्ञान है।

शंकराचार्य विवाद में निलंबित हुए सिटी मजिस्ट्रेट अग्निहोत्री के खिलाफ होगी जांच

बरेली (एजेंसी)। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान के विरोध में इस्तीफा दिए जाने के बाद शासन ने उन पर कड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश शासन ने सिटी मजिस्ट्रेट को निलंबित (सस्पेंड) कर दिया है और पूरे मामले की जांच कमिश्नर को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें शामली जिले से संबद्ध (अटैच) कर दिया गया है। 2019 बैच के पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर पांच पन्नों का भावुक पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफा दिया था। अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के पीछे यूजीसी के नए कानून और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ हुई मारपीट को मुख्य कारण बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था में ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और एक विशेष वर्ग के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस्तीफे के बाद डीएम आवास पर हुए घटनाक्रम ने भी तूल पकड़ा, जहां उन्होंने दावा किया कि उन्हें वहां 45 मिनट तक बंधक बनाकर रखा गया और एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद ही उन्हें छोड़ा गया। इसके बाद रात 11 बजे उन्होंने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी को इतनी कड़ी मेहनत से अर्जित पद को अपने गुरु के अपमान के कारण त्यागना पड़ा, यह समाज और सरकार के लिए सोचने का विषय है। शंकराचार्य ने देर रात अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बात की और उनके निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि पूरा सनातनी समाज उनके साथ है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकारी पद से बड़ा स्थान उन्हें धर्म के क्षेत्र में दिया जाएगा। गौरतलब है कि अलंकार अग्निहोत्री अपने कार्यकाल के दौरान पहले भी चर्चा में रहे थे। कानपुर के रहने वाले अग्निहोत्री ने जब अपने कार्यालय में भगवान हनुमान की तस्वीर लगाई थी, तब भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कलेक्ट्रेट में हंगामा किया था। उस दौरान उनकी प्रदर्शनकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। ब्राह्मण समाज और धार्मिक संगठनों के बीच इस इस्तीफे को लेकर काफी चर्चा है, वहीं प्रशासन इसे अनुशासनहीनता की दृष्टि से देख रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

खरगे-राहुल ने की उत्तराखंड के नेताओं के साथ बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को यहां उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में श्री खरगे तथा श्री गांधी के अलावा पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल, उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्य के पूर्व मंत्री हरकसिंह रावत सहित कई प्रमुख नेता मौजूद थे। बैठक में राज्य विधानसभा के अगले साल प्रस्तावित चुनाव को लेकर पार्टी की रणनीति तथा संगठन को मजबूत बनाने जैसे कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया।

सुप्रीम कोर्ट में महाकाल मंदिर की वीआईपी दर्शन याचिका खारिज

-हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा, गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा कलेक्टर ही तय करेंगे

-महाकाल के सामने कोई वीआईपी नहीं

उज्जैन (एजेंसी)। उज्जैन के ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में नेताओं और वीआईपी को प्रवेश देने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई हो चुकी थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही इंदौर हाईकोर्ट का फैसला महाकाल मंदिर समिति पर लागू रहेगा, जिसमें उज्जैन कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया था कि वे तय करें कि कौन वीआईपी है और कौन नहीं।

दरअसल, महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालुओं के गर्भगृह में प्रवेश पर रोक लगाए जाने के बाद इंदौर के अधिवक्ता चिंतन शास्त्री और दर्पण अवस्थी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि देशभर से लाखों श्रद्धालु महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं, जबकि नेता और प्रभावशाली लोग आसानी से गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। मंगलवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने को कहा।

गर्भगृह में प्रवेश का फैसला फिलहाल कलेक्टर करेंगे

करीब छह महीने पहले इंदौर हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया था कि गर्भगृह में किसे प्रवेश मिलेगा, यह तय करने का अधिकार उज्जैन कलेक्टर के पास है। अदालत ने कहा कि यदि कलेक्टर किसी विशेष दिन किसी व्यक्ति को अनुमति देते हैं, तो उसे वीआईपी माना जाएगा।

ढाई साल से बंद है गर्भगृह

दरअसल, 4 जुलाई 2023 को सावन महीने में आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर का गर्भगृह 11 सितंबर 2023 तक बंद कर दिया गया था। उस समय मंदिर समिति ने कहा था कि सावन माह के समाप्त होते ही गर्भगृह आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इसके बाद गर्भगृह खुला नहीं है। महाकाल लोक बनने से पहले मंदिर में रोजाना 20 से 30 हजार श्रद्धालु आते थे। अक्टूबर 2022 में महाकाल लोक बनने के बाद भक्तों की संख्या चार गुना बढ़कर डेढ़ से दो लाख तक पहुंच गई।

बजट सत्र 2026-27 : सर्वदलीय बैठक संपन्न, किरेन रिजिजू बोले-सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार

नई दिल्ली(एजेंसी)। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नियम प्रक्रियाओं के तहत काम करती है और वह सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि बजट सत्र में हर चर्चा बजट पर ही केंद्रित होना चाहिए यह नियम कहता है।

बजट सत्र में सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है उसके बाद अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है। उसके बाद बजट पर चर्चा होती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदस्य कई मुद्दे उठा सकते हैं क्योंकि अभिभाषण में सरकार को लेखाजोखा रखा जाता है।

उन्होंने कहा कि सरकार हर बात सुनने के लिए तैयार है। सिर्फ हंगाम करके अगर विपक्ष सदन को नहीं चलने देती है तो तकलीफ होती है। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार रहती है लेकिन यह बजट सत्र है इसलिए इसमें बजट पर चर्चा करना इसे पास करना एक नियम है। हम लोग नियम से बाहर जाकर कोयी काम नहीं करते हैं। संविधान से देश चलता है कोई अपनी मर्जी से काम नहीं करता है।

रिजिजू ने कहा, 'मैं यह बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। पिछली बार सभी विपक्षी पार्टियों ने मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की मांग की थी और सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया था। हमने चुनाव सुधारों पर चर्चा की जिसमें एसआईआर का मुद्दा भी शामिल था। चुनाव सुधार पर लोकसभा और राज्यसभा में लंबी चर्चा हुई थी जिसमें सभी सदस्यों को पर्याप्त समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि विपक्ष अलग फिर से एसआईआर पर बहस या चर्चा चाहते हैं तो यह बेवजह होगा क्योंकि इस पर पहले ही पूरी तरह से चर्चा हो चुकी है।'

यूजीसी के नए नियमों का देशभर में विरोध

-दिल्ली हेडक्वार्टर की सुरक्षा बढ़ी, यूपी में सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजीं, सरकार बोली- कोई भेदभाव नहीं होगा

-आर-पार की लड़ाई के मूड में सवर्ण समाज

-यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, समान अवसरों को लेकर भेदभाव का आरोप

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स और सवर्ण जाति के लोगों का यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी) के नए नियमों को लेकर विरोध तेज हो गया है। नई दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों को कैंपस के अंदर घुसने से रोकने के लिए बड़ी संख्या में बैरिकेड्स लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, रायबरेली, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज और सीतापुर में छात्रों, युवाओं और कई संगठनों ने जगह-जगह प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। रायबरेली में भाजपा किसान नेता रमेश बहादुर सिंह और गौरक्षा दल के अध्यक्ष महेंद्र पांडेय ने सवर्ण सांसदों को चूड़ियां भेजी हैं। यूपी में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने नए नियमों के विरोध में इस्तीफा दे दिया है। यूजीसी के नए नियमों को लेकर कुमार विश्वास ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर लिखा कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा 'सवर्ण' हूं... मेरा रोंया-रोंया उखाड़ लो राजा। वहीं, पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के विधायक बेटे प्रतीक ने लिखा कि समाज के एक वर्ग को ऐतिहासिक अपराधी बताकर वर्तमान में प्रतिशोध का शिकार बनाया जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर कहा कि किसी को भी इसका गलत इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा। किसी के भी साथ अत्याचार या भेदभाव नहीं होगा।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका

यूजीसी के हाल में जारी नियमों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा अपनाई गई है और संस्थागत सुरक्षा से कुछ श्रेणियों को बाहर कर दिया गया है। याचिका में केंद्र सरकार और यूजीसी को अंतरिम निर्देश देने की मांग की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के तहत बनाए गए समान अवसर केंद्र और समानता समिति बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध हों। याचिका में कहा गया है कि यूजीसी के हाल में अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने संबंधी विनियम, 2026 का नियम 3 (सी) गैर-समावेशी है और जो छात्र एवं शिक्षक आरक्षित श्रेणियों के नहीं हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। विनीत जिंदल द्वारा दाखिल याचिका में इन विनियमों की इन आधार पर आलोचना की गई है कि जाति आधारित भेदभाव को सख्ती से अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के रूप में परिभाषित किया गया है।

यूजीसी के नए नियमों इसलिए विरोध

यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है- प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन्स, 2026। इसके तहत, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें खासतौर पर एससी,एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि, नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र 'स्वाभाविक अपराधी' बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपसों में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेजों में अराजकता पैदा होगी।

डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को संबोधित कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा-

सेना को समय पर आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना डीआरडीओ के लिए सबसे बड़ी चुनौती

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को संबोधित कर कहा कि आधुनिक युद्ध के दौर में केवल सैन्य शक्ति या संसाधन ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि तकनीकी दक्षता, तेज निर्णय क्षमता और नवाचार को अपनाने की गति ही किसी देश को आगे ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि जो देश तेजी से सोचता है, निर्णय लेता है और नई तकनीक को प्रभावी ढंग से लागू करता है, वही युद्ध के मैदान में बढ़त पाता है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में रिसर्च से लेकर प्रोटोटाइप, टेस्टिंग और अंततः डिप्लॉयमेंट तक की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करना आज की सबसे बड़ी जरुरत है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बलों में समय पर आधुनिक उपकरणों को शामिल करना ही हमारी कार्यक्षमता का सबसे महत्वपूर्ण पैमाना होना चाहिए। यही आज की असली चुनौती है, इस चुनौती को डीआरडीओ जैसे संस्थानों को नेतृत्व देकर पूरा करना होगा। उन्होंने हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख कर कहा कि इस अभियान ने साबित कर दिया है कि भारत के स्वदेशी रक्षा सिस्टम हमारी ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत कर रहे हैं। यह सफलता डीआरडीओ के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी टीम के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन वैज्ञानिकों की तकनीक की परीक्षा न केवल प्रयोगशालाओं में, बल्कि युद्ध के मैदान में भी सफलतापूर्वक हो चुकी है। केंद्रीय रक्षामंत्री सिंह ने उत्पादन और उद्योगों के बीच बेहतर समन्वय की जरुरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डीआरडीओ का फोकस डिजाइन और प्रोटोटाइप पर रहता है, जबकि उत्पादन की जिम्मेदारी उद्योगों की होती है, इसलिए इस अंतर को कम करना बहुत जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय मॉडल की तर्ज पर भारत में भी को-डेवलपमेंट अप्रोच अपनाई जानी चाहिए, जिसमें उद्योग डिजाइन के शुरुआती चरण से ही जुड़े हों। उन्होंने वैज्ञानिकों को रिसर्च के क्षेत्र में जोखिम लेने के लिए प्रोत्साहित कर कहा कि जहां निजी क्षेत्र अपनी विश्वसनीयता साबित कर चुका है, वहां से आगे बढ़कर नए और उभरते क्षेत्रों में काम करना चाहिए। डीआरडीओ और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच नॉलेज शेयरिंग का उदाहरण देकर उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 'तेजस' को एक बड़ी उपलब्धि बताया।

अपने संबोधन के अंत में केंद्रीय मंत्री सिंह ने कहा कि दशकों तक भारत की रक्षा जरूरतें विदेशी तकनीक पर निर्भर रहीं, लेकिन आज देश आत्मविश्वास और स्पष्ट दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में डीआरडीओ की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का योगदान निर्णायक होगा, जिससे भारत वैज्ञानिक, रणनीतिक और आत्मबल के स्तर

पर और अधिक सशक्त बनेगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

अमेरिकी स्वार्थ की आंधी में वैश्विक शांति ट्रम्प की टकराव नीति और विश्व व्यवस्था पर संकट

विश्व राजनीति में ऐसी स्वार्थपरक नीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने केवल अपने हितों को सर्वोपरि रखा है तो अंततः उसे वैश्विक असंतोष का सामना करना पड़ा है। आज अमेरिका उसी राह पर चलता दिख रहा है जहां सहयोग की जगह दबदबा और संवाद की जगह धमकी ले रही है।

(लेखक- कांतिलाल मांडोत)

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ती तकरार केवल दो देशों का आपसी विवाद नहीं है। यह पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता और वैश्विक शांति के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक विदेश नीति ने एक बार फिर दुनिया को तनाव के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। अरब सागर में अमेरिकी जंगीपोत की तैनाती और ईरान को खुले तौर पर चेतावनी देना उसी नीति का विस्तार है जिसमें संवाद के बजाय दबाव और शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जा रही है।

ट्रम्प का यह दावा कि ईरान के कई शहर अमेरिकी जंगीपोत की स्ट्राइक रेंज में हैं केवल सैन्य बयान नहीं है। यह एक राजनीतिक संदेश है जो डर के माध्यम से अपनी शर्तें मनवाने की कोशिश को दिखाता है। दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे उसके निशाने पर हैं। इस तरह की बयानबाजी से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष टकराव की भाषा बोल रहे हैं और कूटनीति को हाशिये पर डाल दिया गया है।

ईरान के भीतर की स्थिति भी चिंताजनक है। राजधानी तेहरान सहित कई शहरों में लंबे समय से इंटरनेट बंद है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद पड़ी हैं। बसीज फोर्स द्वारा युवाओं की डोर टू डोर जांच यह दर्शाती है कि सरकार किसी भी संभावित विरोध को जड़ से खत्म करना चाहती है। हालिया प्रदर्शनों में युवाओं की बड़ी भागीदारी ने सरकार को चौंका दिया था। अब उसी डर के कारण व्यापक सख्ती अपनाई जा रही है।

इस पूरे परिदृश्य में अमेरिकी राष्ट्रपति का ईरानी युवाओं के समर्थन का दावा खोखला नजर आता है। जब इंटरनेट बंद है और लोग एक दूसरे से संवाद तक नहीं कर पा रहे हैं तब केवल बयान देने से कोई ठोस मदद नहीं होती। यह दोहरा रवैया ट्रम्प प्रशासन की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है। एक ओर मानवाधिकारों की बात और दूसरी ओर सैन्य दबाव यही विरोधाभास उनकी विदेश नीति की पहचान बन चुका है।

ट्रम्प इससे पहले भी कई देशों के साथ इसी तरह का व्यवहार कर चुके हैं। चाहे वह ईरान के साथ परमाणु समझौते से एकतरफा बाहर निकलना हो या फिर अन्य देशों पर आर्थिक प्रतिबंध थोपना। हर जगह अमेरिका पहले अपने हितों को रखता है और वैश्विक सहमति की अनदेखी करता है। इससे अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की साख कमजोर होती है और शक्ति संतुलन बिगड़ता है।

शांति के नोबेल पुरस्कार की इच्छा रखने वाले ट्रम्प का आचरण इस आकांक्षा से मेल नहीं खाता। किसी भी नेता का मूल्यांकन उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होता है। जब हर मोर्चे पर टकराव बढ़ाया जाए और हर समस्या का समाधान दबाव में देखा जाए तो शांति की बात केवल एक राजनीतिक नारा बनकर रह जाती है।

भारत के संदर्भ में भी अमेरिकी नीति पर प्रश्न उठते हैं। सार्वजनिक मंचों पर मित्रता और रणनीतिक साझेदारी की बातें होती हैं लेकिन कई मौकों पर ऐसे निर्णय लिए गए जो भारत के हितों के खिलाफ जाते हैं। व्यापार से लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक अमेरिका का रवैया अवसरवादी रहा है। यह दर्शाता है कि ट्रम्प प्रशासन के लिए रिश्ते स्थायी नहीं बल्कि जरूरत आधारित हैं।

विश्व राजनीति में ऐसी स्वार्थपरक नीति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं होती। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी महाशक्ति ने केवल अपने हितों को सर्वोपरि रखा है तो अंततः उसे वैश्विक असंतोष का सामना करना पड़ा है। आज अमेरिका उसी राह पर चलता दिख रहा है जहां सहयोग की जगह दबदबा और संवाद की जगह धमकी ले रही है।

ईरान संकट इसका ताजा उदाहरण है। पश्चिम एशिया पहले से ही अस्थिरता से जूझ रहा है। सीरिया यमन और इराक जैसे देशों में संघर्ष के घाव अभी भरे भी नहीं हैं। ऐसे में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकता है। इसका असर केवल सीमित नहीं रहेगा बल्कि ऊर्जा बाजार और वैश्विक अर्थव्यवस्था भी इसकी चपेट में आएगी।

ईरान की जनता खासकर युवा वर्ग इस संघर्ष का सबसे बड़ा शिकार बन रहा है। महंगाई बेरोजगारी और सामाजिक पाबंदियों के बीच उनका भविष्य और भी अनिश्चित होता जा रहा है। सरकार की सख्ती और बाहरी दबाव ने उनकी स्थिति को दोहरी मार में बदल दिया है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी बनती है कि वह सैन्य धमकियों के बजाय मानवीय दृष्टिकोण अपनाए।

ट्रम्प की नीति से अमेरिका की वैश्विक छवि को भी नुकसान पहुंचा है। जिस देश को लोकतंत्र और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था वही आज कई देशों की नजर में अस्थिरता का कारण बनता जा रहा है। मित्र और विरोधी दोनों ही अमेरिका के इरादों को लेकर असमंजस में हैं। यह स्थिति किसी भी महाशक्ति के लिए खतरनाक संकेत है।

विश्व व्यवस्था सहयोग और विश्वास पर टिकी होती है। जब कोई देश बार बार अपने वादों से मुकरता है और केवल ताकत के दम पर फैसले करता है तो यह ढांचा कमजोर पड़ता है। ट्रम्प प्रशासन के दौरान यही कमजोरियां उजागर हुई हैं। चाहे जलवायु समझौते से बाहर निकलना हो या फिर अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों की अनदेखी हर जगह यही प्रवृत्ति दिखती है।

ईरान और अमेरिका के बीच तनाव का समाधान युद्ध नहीं हो सकता। इतिहास बताता है कि युद्ध समस्याओं को खत्म नहीं करता बल्कि नई समस्याओं को जन्म देता है। जरूरत इस बात की है कि बातचीत और कूटनीति को फिर से प्राथमिकता दी जाए। क्षेत्रीय देशों और वैश्विक शक्तियों को मिलकर ऐसा रास्ता निकालना होगा जो शांति और स्थिरता सुनिश्चित करे।

भारत जैसे देशों के लिए भी यह समय सतर्क रहने का है। बदलती वैश्विक राजनीति में संतुलित और स्वतंत्र विदेश नीति ही राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर सकती है। किसी एक शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता भविष्य में जोखिम भरी साबित हो सकती है।

अंत में यह स्पष्ट है कि ट्रम्प की आक्रामक और स्वार्थ आधारित राजनीति से न तो अमेरिका को दीर्घकालिक लाभ होगा और न ही दुनिया को शांति मिलेगी। शक्ति का प्रदर्शन क्षणिक प्रभाव डाल सकता है लेकिन स्थायी समाधान केवल सहयोग और विश्वास से ही निकलता है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाना चाहता है तो उसे टकराव की जगह संवाद और दबाव की जगह साझेदारी का रास्ता चुनना होगा। यही रास्ता विश्व को एक और बड़े संकट से बचा सकता है।

संपादकीय

यूजीसी के नए नियम

यूजीसी के नए नियमों को लेकर यह भ्रम भी दूर किया जाए कि समानता अवसर केंद्रों के सदस्य केवल आरक्षित वर्गों के लोग ही होंगे। इस सबके साथ ही सबसे अधिक आवश्यक यह है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित या फिर आवश्यक हो तो दंडित करने के भी उपाय किए जाएं, ताकि ऐसी शिकायतें न की जा सकें। इससे बड़ी विडंबना और कोई नहीं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी की ओर से लागू किए गए नए नियम इस कारण निशाने पर हैं कि वे बदले की कार्रवाई का जरिया बन सकते हैं। इसकी बड़ी वजह नए नियमों में भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित न किया जाना तो है ही, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई न करने का प्रविधान भी है। चूंकि इन नियमों को लेकर हो रहे विरोध का दायरा बढ़ता जा रहा है और विरोध करने वालों में सत्तारूढ़ भाजपा के नेता भी हैं, इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन पर नए सिरे से विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। इसी के साथ इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और इसके तहत यूजीसी के नए नियमों को सामान्य बनाम अन्य के रूप में रेखांकित करने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में कुछ भ्रम भी फैलाए जा रहे हैं। यूजीसी के नए नियमों के अनुसार सभी शिक्षा संस्थानों को समानता अवसर केंद्र बनाने होंगे, जिनमें एससी-एसटी के साथ ओबीसी वर्ग के छात्र, कर्मचारी और शिक्षक भी अपने खिलाफ जातिगत आधार पर हो रहे भेदभाव की शिकायत कर सकते हैं। पहले के नियमों में केवल एससी-एसटी वर्ग के छात्र ही शामिल थे। यूजीसी के नए नियमों के तहत नस्ल, पंथ, क्षेत्र, जेंडर, दिव्यांगता आदि के आधार पर भी किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। विरोधियों का तर्क है कि इन आधारों पर तो किसी भी वर्ग के छात्र, कर्मचारी या शिक्षक के खिलाफ भेदभाव हो सकता है। चूंकि यह तर्क निराधार नहीं, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि नए नियम केवल एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों के लिए ही नहीं हैं। आखिर नए नियमों में यह प्रविधान शामिल करने में क्या कठिनाई है कि किसी भी वर्ग का छात्र, कर्मचारी या शिक्षक अपने खिलाफ भेदभाव की शिकायत कर सकता है? ऐसे किसी प्रविधान के न होने से यह ध्वनित हो रहा है कि भेदभाव तो केवल सामान्य वर्ग के लोग ही करते हैं। क्या इस धारणा को सही कहा जा सकता है? यूजीसी के नए नियमों को लेकर यह भ्रम भी दूर किया जाए कि समानता अवसर केंद्रों के सदस्य केवल आरक्षित वर्गों के लोग ही होंगे। इस सबके साथ ही सबसे अधिक आवश्यक यह है कि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वालों को हतोत्साहित या फिर आवश्यक हो तो दंडित करने के भी उपाय किए जाएं, ताकि ऐसी अनदेखी न की जाए कि ऐसे कई कानून हैं, जिनका दुरुपयोग बढ़ता जा रहा है। इनमें एससी-एसटी उत्पीड़न के साथ दहेज और यौन हिंसा रोधी कानून प्रमुख हैं। यह ठीक नहीं कि समानता कायम करने वाले नियम समानता के ही सिद्धांत की अनदेखी करते दिखें।

लाला लाजपत रायः जिनकी लाठी ने आज़ादी की नींव और मजबूत की

(लेखक- सुनील कुमार महला)

28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, आर्य समाज के प्रमुख विचारक तथा प्रखर राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। अपनी ओजस्वी वाणी, निर्भीक तेवर और अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी न झुकने वाले व्यक्तित्व के कारण वे जनमानस में 'पंजाब केसरी' (पंजाब का शेर) के नाम से विख्यात हुए। उनकी गर्जना(ओजस्वी भाषण) इतनी प्रभावशाली होती थी कि सभाओं में उपस्थित हजारों लोग एक ही आह्वान पर उनके पीछे चल पड़ते थे। निस्संदेह, वे भारतीय इतिहास के उन तेजस्वी सितारों में से एक हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के फिरोज़पुर ज़िले के धुडीके गाँव (तत्कालीन पंजाब, ब्रिटिश भारत) में हुआ था। उनके पिता मुंशी राधाकृष्ण उर्दू-फ़ारसी के विद्वान थे तथा माता गुलाब देवी एक धार्मिक एवं संस्कारवान महिला थीं। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से कानून की पढ़ाई की। इसी दौरान वे स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों से अत्यंत प्रभावित हुए और लाहौर में आर्य समाज से जुड़ गए। लाला जी का मानना था कि हिंदू धर्म का नैतिक आदर्शवाद जब राष्ट्रवाद के साथ जुड़ता है, तो वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य (सेकुलर स्टेट) की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिशील था। वे दृढ़ता से विश्वास करते थे कि बिना शिक्षा के कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इसी सोच के परिणामस्वरूप उन्होंने युवाओं को राष्ट्रसेवा के लिए तैयार करने हेतु 'सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी' की स्थापना की तथा लाहौर में 'नेशनल कॉलेज' की शुरुआत की, जहाँ आगे चलकर भगत सिंह जैसे महान क्रांतिकारियों ने शिक्षा प्राप्त की।वे सामाजिक सुधारों के प्रबल समर्थक थे। 1890 के दशक के अंत में जब भारत के कई भागों में भीषण अकाल पड़ा, तब लाला जी ने राहत कार्यों का नेतृत्व किया और अनाथ बच्चों के लिए अनेक राहत शिविर एवं अनाथालय स्थापित कराए। वे विधवा पुनर्विवाह, स्त्री शिक्षा और छुआछूत उन्मूलन के लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रहे।राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ मिलकर उन्होंने उग्र राष्ट्रवादी नेताओं की प्रसिद्ध त्रयी 'लाल-बाल-पाल' का गठन किया। वे इस त्रयी के प्रमुख स्तंभ थे। वे हिंदू महासभा से भी जुड़े रहे और सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध मुखर रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में उन्होंने पंजाब के अनेक राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। वर्ष 1907 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें आंदोलनकारी गतिविधियों के कारण बर्मा निर्वासित कर दिया, किंतु पर्याप्त प्रमाण न होने के कारण कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कम लोगों को ज्ञात है कि 1914 से 1919 के बीच लाला लाजपत राय अमेरिका में रहे। वहाँ उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहुँचाया और ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से अमेरिकी जनता को अवगत कराया। इसी दौरान उन्होंने 1917 में 'होम रूल लीग ऑफ अमेरिका' की स्थापना कर अंतरराष्ट्रीय समुदाय से भारत की स्वतंत्रता के लिए नैतिक समर्थन माँगा।उन्होंने बंगाल विभाजन का कड़ा विरोध किया, रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तीखी निंदा की। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया। वर्ष 1926 में वे केंद्रीय विधानसभा के उप-नेता चुने गए। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने बिना किसी भारतीय सदस्य के साइमन कमीशन भारत भेजा, तो लाला लाजपत राय ने विधानसभा में इसका विरोध प्रस्ताव रखा और लाहौर में इसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नेतृत्व किया। इसी दौरान उन्होंने ऐतिहासिक नारा दिया-साइमन वापस जाओ(साइमन गो बैक)। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट के आदेश पर उन पर निर्मम लाठीचार्ज किया गया। गंभीर चोटों के बावजूद उन्होंने अंग्रेज सरकार से कभी क्षमा नहीं माँगी। लाठीचार्ज से पूर्व उनका दिया गया वाक्य-मेरे शरीर पर पड़ी एक-एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील बनेगी।

बाद में ऐतिहासिक सत्य सिद्ध हुआ। चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को लाहौर में उनका निधन हो गया। लाला जी की शहादत से क्षुब्ध होकर ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स को मारकर प्रतिशोध लिया।लाला लाजपत राय न केवल एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि वे भारत को आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाने वाले दूरदर्शी चिंतक भी थे। उनकी लेखनी भी उतनी ही प्रखर थी-यंग इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, भारत का इंग्लैंड पर आरोप, इंडिया विल दू फ्रीडम, भगवद्गीता का संदेश सहित अनेक कृतियाँ उनके विचारों की अमिट धरोहर हैं। वे पंजाब नेशनल बैंक के सह-संस्थापक, आर्य गजट के संपादक और कई शिक्षण-सामाजिक संस्थाओं के प्रेरणास्रोत रहे।अंततः कहा जा सकता है कि पंजाब केसरी लाला लाजपत राय शहादत की वह मशाल हैं, जिनकी लौ भारतीय राष्ट्रवाद को सदैव प्रकाशित करती रहेगी-उन्हें भुला पाना असंभव है।

(सुनील कुमार महला, फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।)

जो हो रहा है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं

हम मनुष्यों की एक सामान्य सी आदत है कि दुःख की घड़ी में विचलित हो उठते हैं और परिस्थितियों का कसूरवार भगवान को मान लेते हैं। भगवान को कोसते रहते हैं कि हे भगवान हमने आपका क्या बिगाड़ा जो हमें यह दिन देखना पड़ रहा है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जीव बार-बार अपने कर्मों के अनुसार अलग-अलग योनी और शरीर प्राप्त करता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक जीवात्मा परमात्मा से साक्षात्कार नहीं कर लेता। इसलिए जो कुछ भी संसार में होता है या व्यक्ति के साथ घटित होता है उसका जिम्मेदार जीव खुद होता है। संसार में कुछ भी अपने आप नहीं होता है। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वह कर्मों का फल है। ईश्वर तो कमल के फूल के समान है जो संसार में होते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होता है। ईश्वर न तो किसी को दु?ख देता है और न सुख। इस संदर्भ में एक कथा प्रस्तुत है? गौतमी नामक एक वृद्धा ब्राह्मणी थी। जिसका एक मात्र सहारा उसका पुत्र था। ब्राह्मणी अपने पुत्र से अत्यंत स्नेह करती थी। एक दिन एक सर्प ने ब्राह्मणी के पुत्र को डंस लिया। पुत्र की मृत्यु से ब्रह्मणी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। पुत्र को डंसने वाले सांप के ऊपर उसे बहुत प्रोध आ रहा था। सर्प को सजा देने के लिए ब्राह्मणी ने एक सपेरे को बुलाया। सपेरे ने सांप को पकड़ कर ब्राह्मणी के सामने लाकर कहा कि इसी सांप ने तुम्हारे पुत्र को डंसा है, इसे मार दो। ब्राह्मणी ने संपरे से कहा कि इसे मारने से मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा। सांप को तुम्ही ले जाओ और जो उचित समझो सो करो। संपेरा सांप को जंगल में ले आया। सांप को मारने के लिए संपेरे ने जैसे ही पत्थर उठाया, सांप ने कहा मुझे क्यों मारते हो, मैंने तो वही किया जो काल ने कहा था। संपेरे ने काल को ढूंढा और बोला तुमने सर्प को ब्राह्मणी के बच्चे को डंसने के लिए क्यों कहा। काल ने कहा ब्राह्मणी के पुत्र का कर्म फल यही था। मेरा कोई कसूर नहीं है। सपेरा कर्म के पहुंचा और पूछा तुमने ऐसा बुरा कर्म क्यों किया। कर्म ने कहा मुझ से क्यों पूछते हो, यह तो मरने वाले से पूछो मैं तो जड़ हूं। इसके बाद संपेरा ब्राह्मणी के पुत्र की आत्मा के पास पहुंचा। आत्मा ने कहा सभी ठीक कहते हैं। मैंने ही वह कर्म किया था जिसकी वजह से मुझे सर्प ने डंसा, इसके लिए कोई अन्य दोषी नहीं है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म को बाणों से छलनी कर दिया और भीष्म पितामह को बाणों की शैय्या पर सोना पड़ा। इसके पीछे भी भीष्म पितामह के कर्म का फल ही था। बाणों की शैय्या पर लेटे हुए भीष्म ने जब श्री कृष्ण से पूछा, किस अपराध के कारण मुझे इसे तरह बाणों की शैय्या पर सोना पड़ रहा है। इसके उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा था कि, आपने कई जन्म पहले एक सर्प को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इसी अपराध के कारण आपको बाणों की शैय्या मिली है। इसलिए कभी भी जाने-अनजाने किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। हम जैसा कर्म करते हैं उसका फल हमें कभी न कभी जरूर मिलता है।

विचार मंथन

जजों द्वारा सरकार के खिलाफ फैसले, सजा और ट्रांसफर तय?

(लेखक- सनत जैन)

भारत में न्याय पालिका को संविधान ने सर्वोच्च स्थान पर रखा है। विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा तथा अंतिम फैसला करने का अधिकार संविधान ने न्यायपालिका को दिया है। अब ऐसा ऐसा लगने लगा है, न्यायपालिका सरकार के अधीन है। सरकार के दबाव में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला करने के लिए बाध्य हैं। यदि जज सरकार की अनुकूलता के अनुसार फैसला नहीं देते हैं, तो पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जजों के ट्रांसफर किए जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी वरिष्ठता क्रम को नजर अंदाज करते हुए, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। उसको लेकर अब विरोध खुलकर सामने आने लगा है। न्यायपालिका की कॉलेजियम व्यवस्था, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। यह स्थिति भारतीय संविधान, लोकतंत्र और न्यायपालिका के अस्तित्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने लगी है। कॉलेजियम की अनुशंसा पर सरकार का विधि मंत्रालय ट्रांसफर आदेश जारी करता है। कॉलेजियम की अनुशंसा में यह उल्लेख होने लगा है, यह अनुशंसा सरकार के अनुरोध पर की गई है। जो अपने आप कॉलेजियम की अधिकारिता को दर्शा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्ज्वल भुइयाँ ने सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका के प्रभाव को स्वीकार किया है। जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग में जिस तरह का हस्तक्षेप सरकार द्वारा किया जा रहा है, उदाहरण स्वरुप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नियुक्ति हुई है। उस नियुक्ति में 56 जजों की वरिष्ठता को नजर अंदाज किया गया। इसके बाद न्यायपालिका में खदर-बदर मची हुई है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जजों को महत्वपूर्ण मामले दिए जा रहे हैं। सीनियर जजों को कम महत्व के मामले दिए जाते हैं। न्यायपालिका में जिस तरीके से न्याय हो रहा है, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। हाल ही में कई जजों के ऐसे ट्रांसफर किए गए हैं, जो उनके फैसलों के कारण हुए हैं। दिल्ली दंगे के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज ने हेट स्पीच को लेकर एक फैसला दिया था। फैसला देने के तुरंत बाद रातों-रात उस जज का ट्रांसफर कर दिया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति श्रीधरन का ट्रांसफर सरकार के अनुरोध पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में किया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह द्वारा एक महिला सेवा अधिकारी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को संज्ञान मे लिया था। हेट स्पीच को लेकर दमोह के एक मामले में कार्यवाही की थी। नर्सिंग कॉलेजों में जो घोटाला हो रहा था, इसकी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। इसी तरह पैरामेडिकल कॉलेज जो बिना किसी मान्यता के चल रहे थे, उन पर रोक लगाई थी। सरकार उनके फेसलों से नाराज थी। कॉलेजियम ने उनका ट्रांसफर छत्तीसगढ़ करने की अनुशंसा की थी। बाद में सरकार के हस्तक्षेप से उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजा गया। जहां पर उनकी वरिष्ठता खत्म हो गई। अब वह चीफ जस्टिस नही बन पाएंगे। ना सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। जबकि छत्तीसगढ़ की वरिष्ठता के आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते थे।

इस तरह के एक नही बहुत सारे मामले, पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिले हैं। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला नहीं दिया, उन जजों को प्रताड़ित करने का काम कॉलेजियम के माध्यम से सरकार द्वारा किया गया है। जिसके कारण न्यायपालिका की साख आम आदमी की नजरों में कम होती चली जा रही है। इस बात का उल्लेख कोई और नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज भुइयां ने सार्वजनिक कार्यक्रम में किया है। जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और पोस्टिंग में कार्यपालिका द्वारा जिस तरह का दबाव कॉलेजियम और जजों के ऊपर बनाया जा रहा है। उनका कहना था, न्यायिक तबादले केवल न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए होने चाहिए। अब ट्रांसफर, पोस्टिंग कार्य पालिका के दबाव में सजा के रूप में की जा रही है। इस दखल को उन्होंने गंभीर चिंता का विषय बताया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है, एक बार न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म हो गई, तो संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना किसी के वश में नहीं होगा। सारे देश के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जिस तरह से सरकार के दबाव में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद न्याय पालिका के ऊपर लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। खुलकर न्यायपालिका की आलोचना होने लगी है। अब न्यायालय में जाने के स्थान पर आम लोग राजनेताओं और गुंडे बदमाशों का सहारा लेने लगे हैं। आम आदमी सार्वजनिक स्थलों पर अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं। अभी यह प्रारंभिक स्तर पर है। न्यायपालिका की विश्वसनीयता, निष्पक्षता तथा संविधान के अनुसार फैसला नहीं होने पर जनता का विश्वास न्यायपालिका पर नहीं रहेगा। ऐसी स्थिति में भीड़ तंत्र स्वयं आकर न्याय करने लगता है। इसको राजनीतिक दलों, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को समझना होगा। हाल ही के वर्षों में श्रीलंका, बांग्ला देश, नेपाल और दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में, जहां न्यायपालिका कमजोर हुई है, सरकारों की दखलंदाजी बढ़ी है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

एमसीएक्स के तिमाही नतीजों से शेयरों में 6 फीसदी से अधिक तेजी

कंपनी का नेट प्रॉफिट 151 फीसदी बढ़ा, शेयर खरीदने की मची लूट

मुंबई । मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एमसीएक्स) के तिमाही नतीजों ने निवेशकों को खुश कर दिया है। दिसंबर तिमाही 2025 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 401 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 160 करोड़ रुपये था। यानी सालाना आधार पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 151 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। एमसीएक्स का दिसंबर तिमाही का रेवन्यू 666 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल इसी तिमाही के 301 करोड़ रुपये से 121 प्रतिशत अधिक है। ऐ बिटा भी इसी दौरान 527 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। ये आंकड़े कंपनी के ऑपरेशन्स की मजबूत स्थिति को दर्शाते हैं। बीएसई में मंगलवार को एमसीएक्स के शेयर 2385.40 रुपये पर खुलने के बाद 2428.30 रुपये तक पहुंचकर 6.38 फीसदी की तेजी पर कारोबार कर रहे थे। यह कंपनी के 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर 2498 रुपये के काफी करीब है। एमसीएक्स का शेयर लंबे समय से निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 6 महीनों में शेयर में 48 फीसदी की तेजी, एक साल में 113 फीसदी, दो साल में 269 फीसदी और पिछले पांच साल में 620 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है। इस प्रदर्शन के कारण इसे एक मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में देखा जाता है।

सरकारी बॉन्ड बाजार में वित्त वर्ष 27 में बढ़ सकता है दबाव

- 30.5 लाख करोड़ तक पहुंच सकती है केंद्र और राज्यों की बॉन्ड सप्लाई

नई दिल्ली । नई विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन योजना के तहत अब राज्यों पर अधिक खर्च का बोझ आया है। इसके चलते अगले वित्त वर्ष 27 में राज्यों को अतिरिक्त उधारी करनी पड़ सकती है। अनुमान है कि केंद्र और राज्यों दोनों की कुल बॉन्ड सप्लाई 30.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसमें केंद्र सरकार की उधारी लगभग 16.5 लाख करोड़ रुपये और राज्यों की उधारी 14 लाख करोड़ रुपये होगी। चालू वित्त वर्ष में कुल सरकारी बॉन्ड सप्लाई लगभग 27 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच रही है, जिसमें राज्यों का हिस्सा 12.45 लाख करोड़ रुपये है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि भारी सप्लाई से यील्ड पर दबाव बढ़ेगा और निवेशकों की चिंता बढ़ सकती है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में राज्यों की बाजार से उधारी तेजी से बढ़ी है।` वित्त वर्ष 26 की पहली छमाही में राज्यों की उधारी 21 फीसदी बढ़ चुकी है। आने वाले वित्त वर्ष में लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपये के सरकारी बॉन्ड मैच्योर होने हैं। इसके कारण नकदी पर असर पड़ सकता है। आरबीआई इसे लंबी अवधि के बॉन्ड में स्विच या ट्रेजरी बिल जारी कर संतुलित कर सकता है। कोटक महिंद्रा एएमसी के अनुसार वित्त वर्ष 27 में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.3 फीसदी के दायरे में रह सकता है। फिर भी, भारी मैच्योरिटी और बढ़ती सप्लाई के कारण बाजार पर दबाव बना रहेगा। आईडीएफसी बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, घरेलू बचत की कमी और बढ़ती बॉन्ड सप्लाई से आरबीआई पर निर्भरता बढ़ गई है। इसके चलते 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 6.60-6.70 फीसदी के दायरे में बनी रहने की संभावना है।

इंश्योरेंस सेक्टर की नजरें बजट पर, टैक्स छूट बढ़ाने की मांग

- पॉलिसीधारकों को मिल सकता है सीधा फायदा!

नई दिल्ली । हाल ही में प्रीमियम पर जीएसटी घटने से इंश्योरेंस सस्ता हुआ है। बंधन लाइफ इंश्योरेंस के एक वे रिष्ठ अधिकारी के अनुसार बदलाव से लोगों के लिए इंश्योरेंस आसानी से उपलब्ध हो रहा है। इंडस्ट्री चाहती है कि प्रोटेक्शन और हेल्थ प्लान्स पर दोनों टैक्स सिस्टम में अधिक लाभ मिले। इससे ज्यादा परिवारों को कवर मिलेगा। ट्रेडिशनल पॉलिसीज में मैच्योरिटी पर टैक्स-फ्री लिमिट 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख की मांग है। यू लिप के लिए भी टैक्स-फ्री मैच्योरिटी 5 लाख तक करने की उम्मीद है। पेंशन प्रोडक्ट्स को ज्यादा समर्थन और सेक्शन 80डी में डिडक्शन बढ़ाने की मांग है। वर्तमान में 60 साल से कम उम्र वालों के लिए 25 हजार और सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार की सीमा है, जिसे दोगुना करने की जरूरत बताई जा रही है। इसी तरह के बदलावों से भारत का फाइनेंशियल फ्यूचर मजबूत होगा और 2047 तक सभी के लिए इंश्योरेंस का लक्ष्य हासिल होगा।

अदाणी समूह और एम्ब्रेयर भारत में क्षेत्रीय विमान निर्माण में करेंगे साझेदारी

- भारत में साझेदारी के माध्यम से लागत प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करने की योजना

नई दिल्ली ।

अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रेयर ने मंगलवार को एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। यह कदम भारत के तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजार में छोटे और मझोले शहरों के हवाई संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन मंत्रालय में आयोजित समारोह में सहयोग की घोषणा की गई। नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि यह सहयोग केवल विमानों के संयोजन तक सीमित नहीं है।

इसमें प्रगतिशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल विकास, सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला और भारत को क्षेत्रीय विमानों का एक विश्वसनीय विनिर्माण केंद्र बनाने की योजना शामिल है।

अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के एक वे रिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस सहयोग के तहत भारत में एक क्षेत्रीय विमान विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। दोनों कंपनियां भारत में क्षेत्रीय परिवहन विमानों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन भी स्थापित करेंगी। अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस के एक अे धिकारी ने कहा कि यह कदम देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। एम्ब्रेयर 150 सीट तक के वाणिज्यिक जेट विमानों का निर्माण करती है और भारत में इस साझेदारी के माध्यम से लागत प्रतिस्पर्धी माहौल तैयार करने की योजना है। इस साझेदारी से अदाणी समूह भारतीय विमानन उद्योग में विमान निर्माण के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है।

बैंकों की हड़ताल: डिजिटल और एटीएम सेवाएं जारी रहेंगी

नई दिल्ली । बैंक यूनियनों की तरफ से मंगलवार को पूरे दिन हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस वजह से बैंक शाखाओं में कामकाज थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो सकता है। कई कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल रहेंगे, लेकिन बैंक और सरकार ने ग्राहकों की परेशानी कम करने के लिए तैयारियां की हैं। बैंकों ने भरोसा दिलाया है कि एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध है और जरूरत पड़ने पर समय पर कैश भरा जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, कार्ड पेमेंट और अन्य डिजिटल सेवाएं सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। सरकारी लेन-देन और अन्य जरूरी बैंकिंग सेवाएं जारी रहेंगी। ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए भी सेवाएं दी जाएंगी। सोमवार को वित्तीय सेवा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें एसबीआई चेयरमैन, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों के एमडी/सीईओ और आईबीए प्रमुख शामिल थे। बैंकों को निर्देश दिए गए कि हड़ताल के बावजूद ग्राहक सेवाएं बिना रुकावट चलती रहें।

भारत और ईयू के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर बनी सहमति

136 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को मिलेगी रफ्तार, वार्ता पूरी

नई दिल्ली । भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच लंबे समय से प्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत पूरी हो गई है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इसकी औपचारिक घोषणा जल्द हो सकती है। रैटिफिकेशन प्रक्रिया में करीब छह महीने लग सकते हैं, जिससे यह समझौता 2027 की शुरुआत से लागू हो सकेगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता भारत के दृष्टिकोण से संतुलित और भविष्य उन्मुख है। समझौते के मसौदे की कानूनी जांच (लीगल स्क्रबिंग) चल रही है। इसका उद्देश्य अगले पांच से छह महीनों में प्रक्रिया पूरी कर हस्ताक्षर करना है। यह भारत का पिछले पांच वर्षों में आठवां व्यापार समझौता होगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे सभी सौदों की जननी बताया है। वित्त वर्ष 2025 में भारत और ईयू के बीच द्विपक्षीय व्यापार 136.53 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत का निर्यात 75.85 अरब डॉलर और आयात 60.68 अरब डॉलर है। इस समझौते से कपड़ा, दवा, स्टील, पेट्रोलियम उत्पाद और मशीनरी पर टैरिफ में कमी होगी। भारतीय कंपनियों को अमेरिका के ऊंचे टैरिफ से होने वाले झटकों से निपटने में मदद मिलेगी और चीन पर निर्भरता कम होगी।

शेयर बाजार तेजी के साथ बंद

सेंसेक्स 319, निफ्टी 126 अंक ऊपर आया

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार में ये उछाल दुनिया भर से मिले अच्छे संकेतों के साथ ही खरीदारी हावी रहने से आया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच व्यापार करार से भी बाजार में उत्साह आया और वह उछला है। दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 319.78 अंक बढ़कर 81,857.48 और 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 126.75 अंक ऊपर आकर 25,175.40 पर बंद हुआ। बाजार में ये तेजी मेटल और बैंकिंग शेयरों के कारण आई। इस कारण निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक , निफ्टी कमोडिटीज , निफ्टी इंडिया डिफेंस निफ्टी पीएसई और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस बढ़त के साथ बंद हुआ। वहीं निफ्टी मीडिया , निफ्टी ऑटो , निफ्टी एफएमसीजी , निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल् के शेयर गिरावट पर बंद हुए।

आज लार्जकैप के साथ ही मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में भी तेजी रही। निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 338 अंक बढ़कर 57,483.65 और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 66.60 अंक उछलकर 16,419.35 पर बंद हुआ।

सेंसेक्स के शेयरों में अदाणी पोर्ट्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील, टेक महिंद्रा, एनटीपीसी, एसबीआई, अल्ट्राटेक सीमेंट, बीईएल, आईसीआईसीआई बैंक, इंडिगो, एलएंडटी, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट, इन्फोसिस, एचसीएल के शेयर लाभ में रहे जबकि एमएंडएम, कोटक महिंद्रा बैंक, एशियन पेंट्स, इटरनल, मारुति सुजुकी, आईटीसी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एचयूएल और भारती एयरटेल के शेयर गिरे। बाजार में आज के सत्र में उतार-चढ़ाव हावी रहा पर

यूरोपीय यूनिया से करार से बाजार को बल मिला पर बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के डर के कारण ऑटो और बेवरेज शेयर नीचे आये।

इससे पहले आज सुबह बाजार गिरावट साथ खुले। सेंसेक्स 81,436 अंक पर लगभग सपाट खुला, लेकिन कुछ ही देर में बिकवाली हावी हो गई। सुबह शुरुआत के बाद सेंसेक्स 424.17 अंक की गिरावट के साथ 81,113.53 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी-50 भी 25,063 अंक पर सपाट खुलने के बाद फिसल गया और 112.60 अंक गिरकर 25,019 पर ट्रेड करता दिखा। यूरोप से गाड़ियों के आयात पर टैरिफ कम किए जाने की संभावनाओं की खबरों से ऑटो सेक्टर के शेयरों पर दबाव बना रहा। वहीं एशियाई शेयर बाजारों में हल्का उतार-चढ़ाव देखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया पर ज्यादा टैरिफ लगाने की चेतावनी दी। इससे निवेशकों की चिंता बढ़ी। शुरुआती गिरावट के बाद दक्षिण कोरिया का कॉपी इंडेक्स संभला और करीब 0.7 फीसद तक ऊपर आया। जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 0.1फीसदी ऊपर था। वहीं सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए।

चीन में चांदी सबसे महंगी, वैश्विक बाजार से 16 डॉलर प्रति औंस महंगी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव लगभग 109 डॉलर प्रति औंस

नई दिल्ली।

सोना और चांदी की कीमतें इस समय रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी हैं। खासतौर पर चांदी की कीमतों में तेजी ने निवेशकों को चौंका दिया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चांदी का भाव लगभग 109 डॉलर प्रति औंस है, जबकि चीन में यह 125 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब चीन में चांदी अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में करीब 45 हजार रुपए प्रति किलो महंगी बिक रही है। भारत में चांदी चीन के मुकाबले लगभग 17 फीसदी सस्ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन में चांदी की बढ़ी कीमतों का मुख्य कारण वहां की बेहद मजबूत मांग है। दुनिया की कुल चांदी आपूर्ति में चीन की हिस्सेदारी 65 फीसदी से अधिक है। यहां चांदी केवल आभूषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि हाजिर (स्पॉट) और वायदा (फ्यूचर्स) बाजार में बड़े पैमाने पर निवेश के लिए भी खरीदी जा रही है। चीनी निवेशक इसे सुरक्षित निवेश मानकर लगातार बड़ी मात्रा में खरीदारी कर रहे हैं, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। चांदी की कीमतों में आई इस तेजी के पीछे चीन की बदली हुई निर्यात नीति भी अहम भूमिका निभा रही है। जनवरी से केवल सरकारी लाइसेंस वाली कंपनियां ही चांदी का निर्यात कर सकती हैं। इसका असर अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई पर पड़ा है और वैश्विक स्तर पर कीमतों को बढ़ावा मिला है। कॉमेक्स पर चांदी की

कीमतों में हाल ही में 8 फीसदी तक की तेजी देखी गई, हालांकि इस दौरान हल्की गिरावट भी दर्ज हुई है। चीन में चांदी की बढ़ी कीमतें और सख्त निर्यात नियम अंतरराष्ट्रीय बाजार पर सीधे असर डाल रहे हैं। निवेशक वैश्विक सप्लाई और चीन की मांग पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे चांदी की कीमतों में भविष्य में भी उतार-चढ़ाव की संभावना बनी हुई है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मंगलवार को भारतीय रुपया 27 पैसे की बढ़त के साथ ही 91.63 पर बंद हुआ। आज सुबह अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में आज सुबह रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 91.80 पर खुला, जो पिछले बंद भाव 91.70 से 10 पैसे अधिक है। यह सुधार शुक्रवार के 92 प्रति डॉलर के सर्वकालिक निचले स्तर के बाद आया है। पिछले सप्ताह रुपया लगातार दबाव में रहा। शुक्रवार को कारोबार के दौरान यह 92 प्रति डॉलर तक गिर गया, हालांकि अंत में मामूली सुधार के साथ 91.90 पर बंद हुआ। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार डॉलर की कमजोरी के कारण रुपये में मामूली बढ़त देखी गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव 6,000 डॉलर पार जाने की संभावना

- केंद्रीय बैंकों की भारी खरीद ने सोने की कीमतों को दिया बढ़ावा

नई दिल्ली ।

सोने की कीमतें सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में इतिहास रचते हुए 5,000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गईं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में यह 6,000 डॉलर तक जा सकती हैं। वै श्विक बाजार के विश्लेषकों ने 2026 के अंत तक सोने की कीमत 5,400 डॉलर होने का अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि अनिश्चितता के कारण सोना और ऊंचाइयों तक जा सकता है। जंग, राजनीतिक खींचतान और आर्थिक अस्थिरता ने निवेशकों को शेयर बाजार से दूर कर दिया है। अमेरिका और नाटो के बीच तनाव, व्यापार शुल्क को लेकर असमंजस और अमेरिकी मध्यावधि चुनाव जैसी घटनाओं ने बाजार की बेचैनी बढ़ा दी है। इस माहौल में सोना निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प बन गया है। केंद्रीय बैंकों की भारी खरीद ने सोने की कीमतों को बढ़ावा दिया है। विश्लेषकों के अनुसार उभरते देश हर महीने औसतन 60 टन सोना खरीद रहे हैं। पोलैंड अपने भंडार को 700 टन तक बढ़ाने की योजना में है, जबकि चीन लगातार 14 महीने से सोना खरीद रहा है। देशों का रुझान डॉलर से दूरी बनाकर सोने की ओर बढ़ रहा है। सोने से जुड़े ईटीएफ में भी भारी निवेश देखा गया। 2025 में गोल्ड ईटीएफ में 89 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निवेश हुआ। ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने की चमक और बढ़ा दी है। भारत और यूरोप में लोग छोटी ईंटें और सिक्के खरीदने में सक्रिय हैं, जबकि गहनों की मांग थोड़ी कम हुई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोने की थोड़ी गिरावट भी निवेशकों के लिए अवसर साबित होगी। फिलहाल वैश्विक शांति और आर्थिक स्थिरता दूर नजर आती है, इसलिए सोना सुरक्षित निवेश और भरोसेमंद संपत्ति के रूप में अपनी चमक बनाए हुए है।

बजट में रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री की मांग: जीएसटी कम होगा तभी उद्योग बढ़ेगा

नई दिल्ली । मटेरियल रिसाइक्लिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एमआरएआई) ने जयपुर में आयोजित तीन दिन के इंटरनेशनल मटेरियल रिसाइक्लिंग कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन 2026 में केंद्रीय बजट में बदलाव की मांग की। एसोसिएशन के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने कहा कि स्क्रैप पर 18 फीसदी उद्योग की ग्रोथ रोक रहा है और बहुत सारी गतिविधिया अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर में जा रही हैं। मेहता ने कहा कि हाई टैक्स की वजह से कैश में ट्रांजेक्शन बढ़ रहे हैं, जिससे स्क्रैप कलेक्शन का पहला स्तर ही फॉर्मल नहीं बन पा रहा। उन्होंने मांग की कि जीएसटी को 5 फीसदी तक घटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स, जैसे यूपीआई, को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि अनऑर्गनाइज्ड सेक्टर को फॉर्मल इकोनॉमी में लाया जा सके। एमआरएआई ने अल्यूमिनियम स्क्रैप पर इंपोर्ट ड्यूटी पूरी तरह हटाने की अपील की। इसके अलावा ई-वेस्ट, प्लास्टिक और टायर सेक्टर्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी (ईपीआर) नियमों को सख्ती से लागू करने की भी मांग की गई। उन्होंने बताया कि देश में स्क्रैप का लगभग एक तिहाई हिस्सा रगपिकर्स, घरों और छोटे वर्कशॉप्स से आता है।

स्विगी के तीसरी तिमाही नतीजों से पहले बाजार में हलचल तेज

- ग्रोथ तेज लेकिन घाटा थमने का नाम नहीं ले रहा

नई दिल्ली। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी गुरुवार को वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही के नतीजे जारी करने जा रही है। नतीजों से पहले बाजार और निवेशकों में हलचल तेज है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मजबूत ग्रोथ के बावजूद क्या कंपनी मुनाफे के करीब पहुंच पाएगी या घाटा और बढ़ेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिसंबर तिमाही में स्विगी का शुद्ध घाटा बढ़कर करीब 983 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 693.6 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था, जबकि पिछली तिमाही में घाटा 953.6 करोड़ रुपयेरहा था। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि फिलहाल घाटा कम होने के बजाय बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि घाटे के बीच कमाई के मोर्चे पर स्विगी की तस्वीर मजबूत दिख रही है। अनुमान है कि तीसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 48 फीसदी बढ़कर करीब 5,909 करोड़ रुपये हो सकता है। तिमाही आधार पर भी रेवेन्यू में लगभग 6 फीसदी की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

सोना 1.59 लाख और चांदी के भाव 3.59 लाख के पार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी रिकॉर्ड तेजी के बाद नरमी देखी गई

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी के वायदा भाव में मंगलवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। घरेलू बाजार में दोनों कीमती धातुएं ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच गईं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना और चांदी रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करते नजर आए, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बीते सत्र में नया उच्च स्तर बनाने के बाद आज इनमें हल्की नरमी देखी गई। एमसीएक्स पर सोने का बेंचमार्क फरवरी कॉन्ट्रैक्ट मजबूत शुरुआत के साथ 2,637 रुपये की तेजी लेकर 1,58,674 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 1,56,037 रुपये था। इस समय सोने का वायदा भाव 2,447 रुपये की तेजी के साथ 1,58,484 रुपये पर कारोबार कर रहा था। कारोबारी सत्र के दौरान सोने ने 1,59,820 रुपये का उच्च स्तर छू लिया, जबकि दिन का निचला स्तर 1,57,500 रुपये रहा। चांदी के वायदा भाव में भी जोरदार तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर चांदी का बेंचमार्क मार्च कॉन्ट्रैक्ट 5,125 रुपये की बढ़त के साथ 3,39,824 रुपये प्रति किलो पर खुला। इसका पिछला बंद भाव 3,34,699 रुपये था। इस समय चांदी का वायदा भाव 21,287 रुपये की तेजी के साथ 3,55,986 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा था। सत्र के दौरान चांदी ने 3,59,800 रुपये प्रति किलो का सर्वोच्च स्तर छू लिया। वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमेक्स पर सोना और चांदी रिकॉर्ड तेजी के बाद आज कुछ नरम पड़े। सोना 5,005.50 डॉलर प्रति औंस पर खुला और खबर लिखे जाने के समय 15.10 डॉलर की गिरावट के साथ 5,067.40 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। हालांकि, इसने दिन में 5,107.90 डॉलर का उच्च स्तर छुआ। वहीं, चांदी 104.01 डॉलर प्रति औंस पर खुली और 4.65 डॉलर की गिरावट के साथ 110.85 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार करती दिखी, जबकि इसका उच्चतम स्तर 117.70 डॉलर रहा।

पीएम ई-ड्राइव सब्सिडी मार्च 2026 के बाद भी रहे जारी: ई-दोपहिया कंपनियां

कंपनियों ने कहा, सब्सिडी हटने पर बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत

नई दिल्ली ।

भारत की इलेक्ट्रिक दोपहिया कंपनियां सरकार से आग्रह कर रही हैं कि पीएम ई-ड्राइव स्कीम की सब्सिडी मार्च 2026 के बाद भी जारी रहे। कंपनियों का कहना है कि सब्सिडी ग्राहकों के लिए वाहन की कीमत कम करती है और अचानक बंद होने पर छोटे समय में मांग पर असर पड़ सकता है। जुपेरिया ऑटो के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि सब्सिडी हटने पर इलेक्ट्रिक स्कूटर की सड़क पर कीमत 6,000 से 12,000 रुपये तक बढ़ सकती है। ईवियम स्मार्ट मोबिलिटी के अधिकारी के अनुसार सब्सिडी का प्रभाव सभी ग्राहकों पर समान नहीं होता। रिटेल ग्राहक जल्दी खरीदारी में सब्सिडी पर निर्भर रहते हैं, जबकि फ्लीट ऑपरेटर और लंबे रूट वाले ग्राहक कुल खर्च, अपटाइम और सर्विस को महत्व देते हैं। उनके अनुसार, बिना सब्सिडी भी बिक्री रुकती नहीं, केवल निर्णय में समय लगता है। कंपनियां यह भी मांग कर रही हैं कि वित्त वर्ष 26 के बाद स्पष्ट मीडियम-टर्म नीति हो, ताकि फैक्ट्रियां बढ़ाई जा सकें, डीलर नेटवर्क मजबूत हो और पार्ट्स देश में ही बनें।

जेलियो ई-मोबिलिटी ने सुझाव दिया कि बजट 2026 में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिले, जिससे टियर-2/3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन सस्ते हों और सब्सिडी पर निर्भरता कम हो।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

भारतीय टीम चौथे टी20 में भी जीत की लय बनाये रखने उतरेगी

विशाखापत्तनम (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम बुधवार को यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले चौथे टी20 क्रिकेट मैच में भी जीत का सिलसिला बनाये रखने उतरेगी। भारतीय टीम ने पहले तीन मैचों में जीत के साथ ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त अपने नाम कर ली है। ऐसे में उसका मनोबल बढ़ा हुआ है और वह वह इस मैच में भी जीत की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। भारतीय टीम बल्लेबाजी के साथ ही गेंदबाजी में भी कीवी टीम पर भारी पड़ी है। भारतीय टीम इस मैच में सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को तीसरे नंबर पर उतार सकती है। इसका कारण है कि सैमस पहले तीन मैचों में पारी की शुरुआत करते हुए असफल रहे हैं। उनकी जगह ईशान किशन को अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत का अवसर मिल सकता है। भारतीय टीम की ओर से अभी तक कप्तान सूर्यकुमार यादव के अलावा अभिषेक शर्मा सहित अन्य बल्लेबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं गेंदबाजी की बात करें तो तेज गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा रहा है पवर स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाये हैं। ऐसे में अगले माह होने वाले टी20 विश्वकप को देखते हुए टीम इनके फार्म में आने की उम्मीद करेगी।

कुलदीप ने अबतक दो मैचों में केवल दो विकेट लिए हैं। उन्होंने प्रति ओवर 9.5 रन लुटाए। पिछले मैच में भी कुलदीप ने तीन महंगे ओवर किए जिनमें उन्होंने 32 रन दिए पर अन्य गेंदबाजों जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पंड्या के अच्छे प्रदर्शन से भारतीय टीम ने विरोधी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर जीत हासिल की। कुलदीप इससे पहले एकदिवसीय सीरीज में भी प्रभावित नहीं कर पाए थे, जिसमें उन्होंने तीन मैचों में तीन विकेट लिए थे।

वरुण को पिछले मैच में आराम दिया गया था पर पहले दो मैच में भी उनकी गेंदबाजी बेअसर रही। ऐसे में ये भी हो सकता है कि इस मैच में रवि बिश्नोई ही उतरें। बिश्नोई ने पिछले मैच में 18 रन देकर दो विकेट लिए थे। इस मैच में वापसी कर रहे ऑलराउंडर अक्षर पटेल उतरते हैं तो उनकी फिटनेस पर भी सबकी नजरें रहेंगी। वह उंगली में चोट के कारण पिछले दो

मैचों से बाहर थे।

भारतीय टीम चाहेगी कि इस मैच से उसके स्पिनर भी लय हासिल कर लें जहां तक बल्लेबाजी की बात है टीम शीर्ष पर बनी हुई है। भारत की बल्लेबाजी पिछले दोनो ही मैचों में आक्रामक रही है। उसने दूसरे और तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में काफी तेजी से रन बनाकर जीत दर्ज की है। इस मैच में भी यही कहानी रह सकती है। इस श्रृंखला में सीरीज में केवल सैमसन ही असफल रहे हैं। वह तीन मैचों में 5.33 की औसत से 16 रन ही बना पाए हैं जिससे टीम में उनके स्थान को लेकर सवाल उठने लग गए हैं पर तिलक वर्मा के बाहर होने से उन्हें इस मैच में भी बनाये रखने की उम्मीदें हैं।

वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड टीम अब तक इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पायी है। उसके बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है। वहीं गेंदबाज भी प्रभावित नहीं कर पाये हैं। तेज गेंदबाज जेकब डफी के अलावा मैट हेनरी , काइल जैमीसन के अलावा स्पिनर मिचेल सैंटनर भी विफल रहे हैं। अब बचे हुए दो मैचों में कीवी टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज बेहतर प्रदर्शन कर टी20 विश्वकप से पहले लय हासिल करने का प्रयास करेंगे।

टीम इस प्रकार है

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, कुदीप यादव, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड: मिशेल सेंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।

ऑस्ट्रेलियाई ओपन में बड़ा उलटफेर, एलिना ने कोको गॉफ का विजय रथ रोका

मेलबर्न (एजेंसी)। विश्व की 12वीं नंबर की खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने मंगलवार को विश्व की तीसरी नंबर की खिलाड़ी और दो बार की ग्रैंड स्लैम विजेता कोको गॉफ को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के अपने पहले सेमीफाइनल में जगह बनाई। 19 बार की डब्ल्यूटीए टूर-स्तरीय विजेता, जिन्होंने अभी तक अपना पहला ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है, ने अपनी जीत की राह में एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए विश्व की नंबर एक खिलाड़ी आर्यना सबलेंका के खिलाफ मुकाबले के लिए जगह पक्की कर ली है।

इस जीत के साथ, एलिना ने अपनी जीत का सिलसिला 10 मैचों तक बढ़ा दिया है। क्वार्टरफाइनल में हुए एकतरफा मुकाबले में उन्होंने गॉफ को सीधे सेटों में 6-1, 6-2 से हराया। यह ग्रैंड स्लैम में उनका चौथा सेमीफाइनल है और ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहला। उनके नाम विंबलडन में दो और यूएस ओपन में एक सेमीफाइनल का रिकॉर्ड है। एलिना, जिन्होंने 2025 में ÷स्वस्थ होने और ऊर्जा प्राप्त करने÷ के लिए अपना सीज़न समय से पहले समाप्त कर दिया था, 31 वर्षीय खिलाड़ी वापसी के बाद से शानदार फॉर्म में हैं।

उन्होंने इस महीने की शुरुआत में ऑकलैंड में अपना 19वां खिताब जीता और अपने करियर की तीसरी सबसे लंबी जीत की लय पर हैं (2017 में उन्होंने लगातार 15 मैच जीते थे, और 2025 में उन्होंने लगातार 11 मैच जीते), जैसा कि डब्ल्यूटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है। उन्होंने अब तक केवल एक सेट गंवाया है, जो ऑकलैंड क्वार्टरफाइनल में सोनाय कार्टल के खिलाफ था। इस जीत के साथ उन्होंने अक्टूबर 2021 के बाद पहली बार डब्ल्यूटीए रैंकिंग में शीर्ष 10 में वापसी की है।

उन्होंने डब्ल्यूटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर कहा कि बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। मातृत्व अवकाश के बाद शीर्ष 10 में वापसी करना हमेशा से मेरा सपना रहा है, यही मेरा लक्ष्य रहा है। इससे पहले, सबलेंका ने 18 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी इवा जोविक के ऑस्ट्रेलियन ओपन के शानदार सफर को चकनाचूर कर दिया और रॉड लेवर एरिना में 90 मिनट से भी कम समय में 6-3, 6-0 से जीत हासिल की।

सबालेंका ऑस्ट्रेलियाई ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची

मेलबर्न । बेलारुस की महिला टेनिस स्टार एरिना सबालेंका जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गयी हैं। सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए अमेरिका कीइवा जोविक को 6-3, 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। ये मैच तेज गरमी में खेला गया। सबालेंका ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और पहले सेट में ही 3-0 की बढ़त बना ली। अमेरिकी खिलाड़ी ने वापसी का प्रयास किया पर असफल रही। कीइवा ने नौवें गेम में ब्रेकअंक के तीन अवसर हासिल किये पर सबालेंका ने अपना दबदबा बनाये रखा। वहीं दूसरे सेट में सबालेंका ने दो अंक लेकर 5-0 की बढ़त बनाई और जैच जीत लिया। सबालेंका ने मैच के कहा, पिछले कुछ दौर में मुझे उभरती खिलाड़ियों से कड़ संघर्ष के बाद जीत मिली। ये मैच भी उन्हीं में से एक था। इस प्रकार के मुकाबले खेलने से ही खेल का स्तर बढ़ता है।

टी20 मुकाबले दिन में कराये जायें : अश्विन

चेन्नई (एजेंसी)। भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर आर अश्विन ने कहा है कि टी20 क्रिकेट मुकाबले दिन के समय होने चाहिये। अभी ये मुकाबले रात में होते हैं। अश्विन ने कहा कि आने वाले समय में मैचों को दिन में रखने से गेंदबाजों को भी सहयता मिलेगी जिससे गेंद और बल्ले के बीच संतुलन बना रहेगा। अश्विन ने कहा कि अभी रात में मैच होने से बल्लेबाज हावी रहते है और बड़ा लक्ष्य भी हासिल कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में भारतीय टीम ने 200 रनों से अधिक का लक्ष्य पांच ओवर पहले ही हासिल कर लिया। जिससे समझा जा सकता है कि ओस के दौरान गेंदबाजी करना कितना कठिन होता है। ऐसे में मैच में गेंदबाजों के लिए कुछ नहीं रह जाता है।

अश्विन ने कहा कि ओस के कारण गेंदबाजों के लिए असर डालना असंभव सा होता है। अश्विन ने पर कहा, 'भारत की बल्लेबाजी के दौरान न्यूजीलैंड के गेंदबाज निराश दिखे थे। ऐसी ओस में टीमों को खेलने के भेजना सहीं नहीं है। ऐसे हालात में क्रिकेट कौशल की जरूरत ही नहीं पड़ती।,' वहीं अगर इन्हीं पिचों पर दोपहर में मैच खेले जायें तो 150 से 170 रन भी मुश्किल से बनें।'अश्विन के अनुसार ओस के कारण अच्छी गेंद पर भी रन बन जाते हैं। इसलिए इस प्रकार के असंतुलन' को हटाना जरुरी हैं। दिन और रात में विकेट में काफी अंतर होता है। भारत में ऐसा होता ठीक नहीं है। बहुत ही गलत है अच्छी गेंद पर भी रन बन जाते हैं और गेंदबाजों के पास कोई विकल्प नहीं बचता। बल्ले और गेंद के बीच का असंतुलन काफी रहता है।,'

अश्विन ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि न्यूजीलैंड अपनी गेंदबाजों में बदलाव के लिए नहीं बढ़ेगा क्योंकि वह जानता है कि गेंदबाजों के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं कई बार ऐसा होता है कि टीमें इस प्रकार के माहौल में हालात नहीं देखते हुए खिलाड़ी को बाहर कर देती हैं। इस दौरान ये नहीं देखा जाता कि खिलाड़ी के हाथ में कुछ नहीं था।

जोस बटलर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, इस मुकाम तक पहुंचने वाले इंग्लैंड के दूसरे खिलाड़ी बने

कोलंबो (श्रीलंका) (एजेंसी)। अनुभवी विकेटकीपर-बल्लेबाज जोस बटलर 400 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले दूसरे इंग्लैंड खिलाड़ी बन गए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने मंगलवार को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ तीसरे वनडे के दौरान यह उपलब्धि हासिल की। 35 वर्षीय खिलाड़ी दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन से ठीक पीछे हैं जिन्होंने इंग्लैंड के लिए सभी फॉर्मेट में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं।

विश्व क्रिकेट के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक एंडरसन ने श्री लायंस के लिए 401 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। इस महान क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट में 991 विकेट लिए हैं। दूसरी ओर बटलर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 14 शतकों के साथ 12291 रन बनाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में बटलर ने 57 मैचों और 100 पारियों में 31.94 की औसत से 2907 रन बनाए हैं। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने सबसे लंबे फॉर्मेट में दो शतक और 18 अर्धशतक बनाए हैं। वनडे में बटलर ने 198 मैचों और 171 पारियों में 39.11 की औसत से 5515 रन बनाए हैं। 35 वर्षीय खिलाड़ी ने 11 शतक और 29 अर्धशतक बनाए हैं।

टी20आई में बटलर ने 144 मैचों और 132 पारियों में 35.49 की औसत से 3869 रन बनाए हैं। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने 1 शतक और 28 अर्धशतक

लगाए हैं। दो बार ICC व्हाइट-बॉल खिताब जीत चुके बटलर आगामी ICC पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का भी हिस्सा हैं, जो 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहा है। इंग्लैंड ने आगामी ICC टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें स्टार बल्लेबाज हैरी ब्रूक को कप्तान बनाया गया है। इंग्लैंड 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ अपने टी20 वर्ल्ड कप 2026 अभियान की शुरुआत करेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंग्लैंड टीम

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, जेमी ओवरटन, आदिल राशिद, फिल साल्ट, जोश टंग, ल्यूक वुड।

पीसीबी प्रमुख नकवी ने बांग्लादेश को विश्वकप बहिष्कार के लिए भड़काया : राजीव शुक्ला

मुम्बई । भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को टी20 विश्कवप का बहिष्कार करने के लिए उकसाया था। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया है कि इस सब के पीछे पीसीबी प्रमुख मोहसिन नक़वी हैं। नकवी ने ही बीसीबी को भारत में नहीं खेलने के लिए भड़काया था। टी20 विश्वकप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। बंग्लादेश बोर्ड ने सुरक्षा कारणों से भारत में इस टूर्नामेंट को खेलने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने उसकी जगह पर स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल कर लिया था। शुक्ला ने कहा कि पीसीबी ने इस मामले में एक प्रकार से साजिश की है। उन्होंने कहा, पीबीबी ने बिना किसी कारण के इस मामले में बांग्लादेश को भड़कायाहै। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने पूर्व में बांग्लादेश के लोगों पर क्या अत्याचार किए हैं और अब वे उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पूरी तरह गलत है। शुक्ला ने साफ कहा कि बीसीसीआईइ्ड चाहती थी कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में खेले। हम चाहते थे कि बांग्लादेश खेले और हमने उन्हें पूरी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया था प जब उन्होंने यह फैसला ले लिया, तो अंतिक समय पर कार्यक्रम में बदलाव करना संभव नहीं था। इसी वजह से स्कॉटलैंड को शामिल किया गया।

अंडर-19 वर्ल्ड कप में वैभव सूर्यवंशी का तूफान, जिम्बाब्वे के खिलाफ ठोका शानदार अर्धशतक

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय अंडर-19 टीम के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर अपने आक्रामक खेल से सुर्खियों में आ गए हैं। अंडर-19 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए अहम मुकाबले में वैभव ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाज़ी करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा। उनकी यह पारी भले ही शतक में नहीं बदल सकी, लेकिन भारत को मजबूत शुरुआत दिलाने में निर्णायक साबित हुई। लगातार दूसरे मैच में फिफ्टी लगाकर वैभव ने यह साफ कर दिया है कि वह इस टूर्नामेंट में भारत के सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक हैं।

पावरप्ले में वैभव का आक्रामक तेवर

बुलवायों में खेले जा रहे इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही जिम्बाब्वे के गेंदबाज़ों पर दबाव बना दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए बड़े शॉट खेलने शुरू किए और मैदान के चारों ओर रन बटोरे। उनकी बल्लेबाज़ी में आत्मविश्वास और आक्रामकता साफ झलक रही थी, जिससे जिम्बाब्वे की टीम बैकफुट पर चली गई।

30 गेंदों में 52 रन, स्ट्राइक रेट ने मचाया धमाल

वैभव ने इस मैच में सिर्फ 30 गेंदों का सामना करते हुए 52 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से चार चौके और चार लंबे छक्के निकले। 173.33 के स्ट्राइक रेट से खेली गई यह पारी टी20 अंदाज़ की याद दिलाने वाली थी, जिसने भारत को तेज़ शुरुआत दी। जब वैभव आउट हुए, तब टीम का स्कोर 101 रन था, जिसमें आधे से ज़्यादा रन अकेले उनके खाते में थे।

एरॉन जॉर्ज और कप्तान आयुष म्हात्रे का योगदान

वैभव के साथ पारी की शुरुआत करने वाले एरॉन जॉर्ज ने भी शुरुआती ओवरों में तेज़ बल्लेबाज़ी की। उन्होंने 16 गेंदों में दो चौके और एक छक्के की मदद से 23 रन बनाए, जिससे भारत की रनगति बनी रही। इसके बाद कप्तान आयुष म्हात्रे क्रीज पर आए और उन्होंने 19 गेंदों में 21 रन जोड़े। अपनी पारी में कप्तान ने एक चौका और दो छक्के लगाए। हालांकि, कप्तान के आउट होने के तुरंत बाद वैभव भी पवेलियन लौट गए, जिससे भारत को एक साथ दो झटके लगे।

वर्ल्ड कप में दूसरा अर्धशतक, लगातार दिखा दम

जिम्बाब्वे के खिलाफ यह अर्धशतक वैभव सूर्यवंशी का अंडर-19 वर्ल्ड कप में दूसरा अर्धशतक रहा। इससे पहले उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाज़ी करते हुए 72 रन बनाए थे। उस पारी में उन्होंने 67 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के लगाए थे। हालांकि वह पारी अपेक्षाकृत धीमी थी, लेकिन उसमें शतक की पूरी उम्मीद नजर आ रही थी।

अनिश्चितता ही वैभव की सबसे बड़ी ताकत

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाज़ी की सबसे बड़ी खासियत उनकी अनिश्चितता है। जिस अंदाज़ में वह शॉट्स खेलते हैं, उससे गेंदबाज़ और फील्डर दोनों ही अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि अगली गेंद पर क्या होने वाला है। यही वजह है कि वह विपक्षी टीम पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं।

महिला प्रीमियर लीग अंक तालिका में आरसीबी शीर्ष पर बरकरार

नवी मुम्बई । रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) की टीम पिछले दो मैचों में मिली हार के बाद भी महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में नंबर एक पर बनी हुई है। टीम को अबतक पांच जीत मिली है। आरसीबी ने पहले ही प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है हालांकि लीग चरण के अंतिम दो मुकाबलों में उसे हार मिली थी। इससे टीम का फाइनल तक का प्रवेश बाधित हुआ है। हालांकि अभी भी टीम अंक तालिका में सबसे ऊपर है। अन्य कोई टीम अभी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पायी है। अब तक आरसीबी के सबसे अधिक 10 अंक हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मुंबई इंडियंस के 6 अंक पर पर ये उसने 7 मैचों में हासिल किये हैं। गुजरात जायंट्स के भी 6 अंक हैं पर नेट रन रेट मुम्बई का अधिक होने के कारण वह दूसरे नंबर पर है। गुजरात तीसरे और दिल्ली कैपिटल्स चौथे नंबर पर है। दिल्ली की टीम भी 6 में से 3 मुकाबले जीतकर तीसरे नंबर पर है। वहीं यूपी वॉरियर्स 6 में से 2 ही मुकाबले जीतकर अंतिम स्थान पर है। अब यूपी वॉरियर्स के पास प्लेऑफ के लिए जगह बनाने का अंतिम अवसर है पर इसके लिए यूपी को अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे। इनमें से उसका एक मैच आरसीबी और एक मैच दिल्ली के खिलाफ है। अभी आरसीबी के क्वालीफाई करने के बाद भी चारों टीमों के पास प्लेऑफ में जगह बनाने का अवसर है। इसमें दूसरे और तीसरे नंबर की टीम को एलिमिनेटर खेलना है, जबकि शीर्ष पर रहने वाली टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी।

एचआईएल 2025-26: हॉकी इंडिया लीग फाइनल में कलिंगा लांसर्स की जीत, दूसरी बार बने चैंपियन

भुवनेश्वर (एजेंसी)। हॉकी इंडिया लीग (HIL) 2025-26 का खिताब ने अपने नाम कर लिया। भुवनेश्वर में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में लांसर्स ने रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। घरेलू दर्शकों के सामने खेले गए इस मुकाबले में बेल्जियम के ड्रैग-फ्लिक विशेषज्ञ अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स ने शानदार प्रदर्शन किया।

अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स की चमक, दिलप्रीत ने दिया अहम योगदान

फाइनल में अलेक्जेंडर हेंड्रिक्स (4वें और 27वें मिनट) ने दो शानदार गोल दागकर कलिंगा लांसर्स की जीत की नींव रखी। इसके अलावा दिलप्रीत सिंह (25वां मिनट) ने रिबाउंड पर तेजी दिखाते हुए गोल कर टीम को मजबूत बढ़त दिलाई।

रांची रॉयल्स की ओर से अराइजीत सिंह हुंडाल (9वां मिनट) और कप्तान टॉम बून (59वां मिनट) ने गोल किए, लेकिन टीम जीत तक नहीं पहुंच सकी।

तेज़ रफ्तार से शुरू हुआ फाइनल मुकाबला

फाइनल मैच की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। दोनों टीमों ने शुरुआती मिनटों से ही लगातार सर्कल एंट्री बनाईं। चौथे मिनट में कलिंगा लांसर्स को पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिस पर हेंड्रिक्स ने ताकतवर ड्रैग-फ्लिक से गोल कर अपनी टीम को बढ़त दिलाई।

हुंडाल का शानदार जवाब, स्कोर हुआ बराबर

हालांकि लांसर्स की बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। नौवें मिनट में यशदीप सिवाच ने लेफ्ट फ्लैंक से शानदार पास निकाला, जिसे अराइजीत सिंह हुंडाल ने बेहतरीन कंट्रोल के बाद गोल में तब्दील कर स्कोर 1-1 कर दिया।

दूसरे क्वार्टर में लांसर्स का दबदबा

दूसरे क्वार्टर में कलिंगा लांसर्स ने लगातार दबाव बनाया और कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। 25वें मिनट में हेंड्रिक्स के ड्रैग-फ्लिक को गोलकीपर सूरज करकेरा ने रोका, लेकिन दिलप्रीत सिंह ने रिबाउंड पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए गोल दाग दिया।

इसके दो मिनट बाद ही हेंड्रिक्स ने एक और सटीक ड्रैग-फ्लिक के जरिए स्कोर 3-1 कर दिया और लांसर्स हाफ टाइम तक मजबूत स्थिति में पहुंच गए।

दूसरे हाफ में रांची की जोरदार वापसी की कोशिश

ब्रेक के बाद रांची रॉयल्स ने गेंद पर ज्यादा नियंत्रण रखा और संयम के साथ वापसी की कोशिश की। 36वें मिनट में मिले पेनल्टी कॉर्नर पर कप्तान टॉम बून का शॉट पहले रशर ने रोक दिया। तीसरे क्वार्टर के अंत में हुंडाल को गोल का बेहतरीन मौका मिला, लेकिन कलिंगा लांसर्स के गोलकीपर कृष्ण बहादुर पाठक ने शानदार बचाव कर टीम को राहत दी।

आखिरी क्वार्टर में पाठक बने दीवार

चौथे क्वार्टर में खेल लगभग पूरी तरह कलिंगा लांसर्स के हाफ में सिमट गया। रांची रॉयल्स ने लगातार हमले किए, लेकिन कृष्ण बहादुर पाठक ने सैम लेन, टॉम बून और नीलम संजीप जेस के शॉट्स को रोकते हुए कई बेहतरीन सेव कीं।

59वें मिनट में टॉम बून ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर स्कोर 3-2 किया, लेकिन समय की कमी के चलते रांची बराबरी नहीं कर सकी।

कलिंगा लांसर्स का दूसरा HIL खिताब

यह कलिंगा लांसर्स का दूसरा हॉकी इंडिया लीग खिताब है। इससे पहले टीम ने 2017 में भी चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया था। दिन के पहले मुकाबले में हैदराबाद तूफान्स ने HIL GC को 4-3 से हराकर तीसरा स्थान हासिल किया।

HIL 2025-26 के व्यक्तिगत पुरस्कार

फेयरप्ले अवॉर्ड: HIL GC

बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट: प्रिंस दीप सिंह (तमिलनाडु ड्रैगन्स)

इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: तालिम प्रियबर्ता (HIL GC)

टॉप स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट: टॉम बून (19 गोल)

प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट: अमनदीप लकरा (हैदराबाद तूफान्स)

स्कॉटलैंड ने टी20 विश्वकप के लिए घोषित की टीम, बेरिंगटन करेंगे कप्तानी

एडिनबर्ग । स्कॉटलैंड ने अगले माह होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप क्रिकेट 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश के विश्वकप से हटने के बाद स्कॉटलैंड को शामिल किया है। इस टूर्नामेंट में स्कॉटलैंड की कप्तानी रिची बेरिंगटन करेंगे। 15 सदस्यीय टीम के साथ ही जैस्पर डेविडसन और जैक जार्विस को ट्रैवल रिजर्व के तौर पर रखा गया है। वहीं मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर टीम में रखे गये हैं। स्कॉटलैंड की टीम को बांग्लादेश की जगह पर टूर्नामेंट के ग्रुप सी में रखा गया है। इस ग्रुप में स्कॉटलैंड के साथ वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल की टीमें भी शामिल हैं। स्कॉटलैंड को अपने सभी लीग मैच भारत में खेलने हैं। टीम को तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम में जबकि उसका अंतिम आखिरी लीग मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोपहर 3:00 बजे से खेलना है। वहीं 09 फरवरी को इटली से भी कोलकाता में ही खेलना है पर ये मैच सुबह 11 बजे शुरु होगा। वहीं उसका 14 फरवरी को इंग्लैंड से मुकाबला भी कोलकाता में दोपहर तीन बजे से होगा। उसका अंति मैच 17 फरवरी को कोलकाता में नेपाल के खिलाफ शाम 7 बजे से होगा।

टीम इस प्रकार है : रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैकक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलन, जॉर्ज मुन्सी, सफयान शरीफ, मार्क वाट, ब्रैडली व्हील।

ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर : जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस।

नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर : मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

यूएन में भारत का कड़ा रुख : पाकिस्तान को खूब सुनाई कहा– ऐसे नहीं देंगे सिंधू का पानी

जेनेवा (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी आतंकी नीतियों और भारत विरोधी एजेंडे के लिए जमकर लताड़ लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पार्वथनेनी हरीश ने दो टूक शब्दों में कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र एजेंडा भारत को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन उसे अब अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना होगा। सिंधु जल संधि पर भारत का रुख अब बेहद सख्त नजर आ रहा है। भारत ने स्पष्ट किया कि उसने 65 साल पहले सद्भावना के साथ यह संधि की थी, लेकिन पाकिस्तान ने तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले करके इस भरोसे को तोड़ा है। भारत ने अब घोषणा की है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को स्थायी रूप से खत्म नहीं कर देता, तब तक इस संधि को रोक कर रखा जाएगा। अंत में, भारत ने पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति और वहां के संवैधानिक संकट पर भी कटाक्ष किया। पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को दूसरों को ज्ञान देने के बजाय आत्मचिंतन करना चाहिए कि कैसे वहां सेना ने 27वें संशोधन के जरिए संवैधानिक तख्तापलट किया और अपने रक्षा प्रमुख को आजीवन छूट दे दी। भारतीय प्रतिनिधि ने पिछले साल के घटनाक्रमों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के उस झूठे नैरेटिव को सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुद के पक्ष में विवरण पेश किया था। पी हरीश ने याद दिलाया कि कैसे पाकिस्तान की हेकड़ी कुछ ही घंटों में गायब हो गई थी। उन्होंने कहा, 9 मई तक पाकिस्तान भारत पर और अधिक हमलों की धमकी दे रहा था, लेकिन 10 मई की सुबह होते-होते पाकिस्तानी सेना ने सीधे भारतीय सेना को फोन किया और युद्ध रोकने (सीजफायर) की गुहार लगानी शुरू कर दी। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए उन साक्ष्यों का भी जिक्र किया जो पाकिस्तानी सेना की विफलता की कहानी बयां करते हैं। भारतीय कार्रवाई से पाकिस्तान के कई एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा था। नष्ट हुए रनवे और जले हुए हैंगर्स की तस्वीरें आज भी जनता के सामने मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी को उजागर करती हैं।

बांग्लादेश की समीक्षा समिति ने अनुबंध रद्द करने की सिफारिश की, अब महंगी बिजली देंगे आडानी

ढाका (एजेंसी)। बांग्लादेश की एक उच्चस्तरीय समीक्षा समिति ने भारतीय समूह अडानी पावर के साथ हुए अरबों डॉलर के बिजली आपूर्ति समझौते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार को जारी अपनी रिपोर्ट में समिति ने इस सौदे में गंभीर विसंगतियों का दावा करते हुए इसे रद्द करने या इसकी शर्तों पर दोबारा बातचीत करने की सिफारिश की है। यह समझौता वर्तमान में बांग्लादेश की कुल बिजली आवश्यकता का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा पूरा करता है। नेशनल रिव्यू कमेटी ऑन पावर परचेज एग्रीमेंट्स द्वारा तैयार की गई यह रिपोर्ट उन सौदों की जांच का हिस्सा है, जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान किए गए थे। रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड बिजली के लिए जो कीमत चुका रहा है, वह वास्तविक बाजार मूल्य से लगभग 50 प्रतिशत अधिक है। समिति के अनुसार, झारखंड के गोड्डा प्लांट से होने वाली आपूर्ति के लिए प्रति यूनिट 4 से 5 सेंट की अतिरिक्त कीमत वसूली जा रही है। रिपोर्ट में इसे महज एक तकनीकी गलती न मानकर राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यवसायियों के बीच व्यवस्थित मिलीभगत का परिणाम बताया गया है। झारखंड स्थित 2 अरब डॉलर की लागत वाला अडानी का कोयला आधारित गोड्डा प्लांट 2024 में पूरी तरह चालू हुआ था। यह 25 वर्षीय अनुबंध के तहत बांग्लादेश की 13 गीगावॉट की आधारभूत मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा करता है, जिसके बदले बांग्लादेश सालाना करीब 1 अरब डॉलर का भुगतान करता है। समिति ने चिंता जताई है कि वर्ष 2024-25 में बीपीडीबी को 4.13 अरब डॉलर का भारी घाटा हुआ है, जिसका एक बड़ा कारण ये महंगे अनुबंध हैं।

सुरक्षा और ड्रग तस्करी रोकने के लिए भारत-अमेरिका का नया वर्किंग ग्रुप गठित

वाशिंगटन (एजेंसी)। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने ड्रग तस्करी और नशों से जुड़े आतंकवाद (नार्को-टेररिज्म) की कमर तोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक संयुक्त तंत्र की शुरुआत की है। इस रणनीतिक पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और समाज को सिंथेटिक नशों के बढ़ते खतरे से सुरक्षित बचाना है। व्हाइट हाउस द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यूएस-इंडिया ड्रग पॉलिसी एग्जीक्यूटिव वर्किंग ग्रुप की पहली महत्वपूर्ण बैठक 20 से 21 जनवरी को वाशिंगटन में संपन्न हुई। इस उच्चस्तरीय बैठक की शुरुआत करते हुए अमेरिका के राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण नीति कार्यालय की निदेशक सारा कार्टर ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा सहयोग को लेकर एक समान विजन रखते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशीले पदार्थों का संकट अब केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। यह नया कार्य समूह दोनों देशों की विशेषज्ञता और खुफिया जानकारी साझा करने की साझेदारी का उपयोग कर परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और अवैध नेटवर्क को ध्वस्त करेगा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने इस अवसर पर भारतीय प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी रोकना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने विशेष रूप से उन रसायनों (प्रीकर्सर केमिकल्स) के अवैध डायवर्जन से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया, जिनका उपयोग सिंथेटिक ड्रग्स बनाने में किया जाता है। भारत का लक्ष्य एक ऐसा संतुलन बनाना है जिसमें कानून का सख्ती से पालन हो और साथ ही वैध फार्मास्युटिकल उद्योग व व्यापार में कोई बाधा न आए।

अमेरिका के दो युद्धपोत पहुंचते ही भड़का ईरान कहा- हमें कमजोर न समझें, हम तबाही मचा देंगे

तेहरान (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पिछले सप्ताह जहां कुछ मुस्लिम देशों की मध्यस्थता के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होता दिख रहा था, वहीं हालिया घटनाक्रम ने स्थिति को बेहद विस्फोटक बना दिया है। सोमवार को अमेरिका के तीन शक्तिशाली युद्धपोतों के पश्चिम एशिया पहुँचने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर भीषण जंग के मुहाने पर खड़ा है। इससे भड़े ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि हमें कमजोर न समझें, हम तबाही मचा देंगे।

रणनीतिक तैनाती और ट्रंप का रुख अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की है कि तीन विध्वंसक जहाजों के साथ एक विमानवाहक पोत को क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के नाम पर तैनात किया गया है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में इसे ईरान के खिलाफ एक सीधी सैन्य तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों पर की जा रही दमनकारी कार्रवाई के विरोध में वे हवाई हमले का विकल्प चुन सकते हैं।

ट्रंप ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि जहाजों का एक विशाल बेड़ा उस दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि उन्होंने इसे एक एहतियाती कदम बताया है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि ईरान ने अपनी जनता पर हिंसा बंद नहीं की, तो अमेरिका हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होगा।

ईरान में हिंसक दमन और गृहयुद्ध जैसे हालात ईरान में आर्थिक तंगी और बेतहाशा बढ़ती महंगाई को लेकर पिछले महीने शुरू हुआ जन-आक्रोश अब एक बड़े विद्रोह का रूप ले चुका है। खामेनेई शासन के विरुद्ध सड़कों पर उतरे लोगों पर सुरक्षा बलों ने कड़ी कार्रवाई की है। विभिन्न रिपोर्ट्स के अनुसार, इन प्रदर्शनों में अब तक 5000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इसी हिंसक कार्रवाई को आधार बनाकर अमेरिका अब ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ा रहा है। अमेरिकी तैनाती के जवाब में ईरान ने भी कड़े तेवर दिखाए हैं, कहा है कि हवा का जवाब बवंडर से देंगे। तेहरान के एक मुख्य चौक पर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें एक अमेरिकी विमानवाहक पोत को तबाह होते हुए दिखाया गया है। इस पोस्टर पर साफ शब्दों में लिखा है– हवा का जवाब बवंडर से दिया जाएगा। ईरान के अर्द्धसैन्य बल रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर ने भी हुंकार भरते हुए कहा है कि उनकी सेना की उंगलियां ट्रिगर पर हैं और वे किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ती इस जुबानी जंग और समुद्र में सैन्य हलचल ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है।

इजरायली बंधकों की वापसी और गाजा के पुनर्निर्माण व शांति की अमेरिका ने की तारीफ

वाशिंगटन। व्हाइट हाउस ने गाजा के पुनर्निर्माण में मदद के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय तंत्र के गठन को मिडिल ईस्ट में विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि बताया है। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हुए प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा कि ट्रंप ने गाजा से बंधकों के आखिरी बचे हुए शव की वापसी तय करने में मदद की है। लेविट ने कहा कि यह घटनाक्रम न सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि व्यापक क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी अहम है। उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रपति ट्रंप, अमेरिका, हमारे सहयोगियों और मिडिल ईस्ट में शांति के लिए बहुत अच्छी खबर है। उन्होंने आगे कहा कि 20 से ज्यादा देशों ने गाजा के पुनर्निर्माण पर केंद्रित एक नए स्थापित बोर्ड ऑफ पीस पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल महीनों के तीव्र संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में सहायता के लिए एक समन्वित अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस के गठन को भी ट्रंप प्रशासन की एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने निरंतर कूटनीतिक प्रयासों से असंभव को संभव कर दिखाया है। लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप व्यक्तिगत रूप से मिडिल ईस्ट शांति प्रयासों को लेकर व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हैं। वे गाजा को स्थिर करने व हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक साझेदारों के साथ लगातार संवाद कर रहे हैं। गाजा संघर्ष मिडिल ईस्ट में सबसे अस्थिर और बारीकी से देखे जाने वाले संकटों में से एक है, जिसमें मानवीय मुद्दे, क्षेत्रीय सुरक्षा जोखिम और वैश्विक कूटनीति जटिल तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। भारत और पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों पर नजर रखने वाले अन्य देशों के लिए गाजा के पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय कूटनीति में अमेरिका की बदलती भूमिका को व्यापक मिडिल ईस्ट स्थिरता और भविष्य की शांति पहलों के लिए अहम माना जा रहा है।

अमेरिकी मंसूबों को झटका: सऊदी, कतर और यूएई ने सैन्य सहयोग से किया इनकार

तेहरान (एजेंसी)। मध्य पूर्व की भू-राजनीति में एक बड़ा और अप्रत्याशित मोड़ आया है। ईरान में सत्ता परिवर्तन (रिजीम चेंज) और उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वाकांक्षी योजना को अपने ही सहयोगियों से कड़ा झटका लगा है। खाड़ी के तीन प्रमुख मुस्लिम देशों– सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और कतर ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि वे ईरान पर किसी भी सैन्य हमले के लिए अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देंगे। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन की सैन्य रणनीति को अधर में लटका दिया है और ये देश अनजाने में ईरान के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में उभर रहे हैं।

वाशिंगटन और तेहरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में यूएसएस अब्राहम लिंकन जंगी बेड़े और परमाणु सक्षम बमवर्षकों की तैनाती की है। अमेरिका का तर्क है कि ईरान में जारी प्रदर्शनों के खिलाफ सरकार की दमनकारी कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों को दी जा रही फांसी के विरोध में वह सैन्य विकल्प अपना सकता है। हालांकि, इन धमकियों का असर तब कम होता दिखा जब खाड़ी के देशों ने अमेरिका को बेस और एयरस्पेस देने से मना कर दिया। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपनी संप्रभुता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। यूएई ने स्पष्ट किया कि वह अपनी सीमा का उपयोग किसी भी शत्रुतापूर्ण सैन्य कार्रवाई या लॉजिस्टिक सहायता के लिए नहीं होने देगा। वहीं, सऊदी अरब ने भी निजी स्तर पर अमेरिका को सूचित किया है कि वह अपने हवाई क्षेत्र को ईरानी हमले के लिए बंद रखेगा। यह सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईरान तक पहुंचने का सबसे छोटा और सुगम रास्ता सऊदी अरब के ऊपर से गुजरता है। यदि सऊदी एयरस्पेस बंद रहता है, तो अमेरिकी विमानों को लंबा और खर्चीला चक्कर काटना पड़ेगा, जिससे ऑपरेशन की जटिलता बढ़ जाएगी।

ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है अमेरिका- जंगी जहाज समंदर में उतरे, हमले के लिए ठिकाने भी चिन्हित

वाशिंगटन (एजेंसी)। मध्य पूर्व में एक बार फिर युद्ध की आहट तेज हो गई है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी नौसेना का विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन तीन अन्य घातक युद्धपोतों के साथ पश्चिम एशिया के रणनीतिक जलक्षेत्र में तैनात हो चुका है। इस भारी सैन्य जमावड़े ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है। अपुष्ट खबरों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को एक सुरक्षित बंकर में स्थानांतरित कर दिया गया है और प्रशासन की कमान फिलहाल उनके बेटे के हाथों में होने की चर्चा है। हालांकि अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने इस तैनाती को केवल क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने का एक कदम बताया है, लेकिन कूटनीतिक गलियारों में इसे ईरान पर एक निर्णायक प्रहार की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।

सैन्य सूत्रों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि अमेरिका ने ईरान के उन वरिष्ठ अधिकारियों और ठिकानों को चिन्हित किया है, जो दमनकारी नीतियों और क्षेत्रीय अस्थिरता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। खुफिया इनपुट के अनुसार, वर्तमान में ईरान की आंतरिक स्थिति 1979 की क्रांति के बाद के सबसे कमजोर दौर से गुजर रही है। देश न केवल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बल्कि शासन की जनता पर पकड़ भी पहले के मुकाबले काफी ढीली हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुफिया एजेंसियों ने सूचित किया है कि यह ईरान की सैन्य और रणनीतिक क्षमताओं को कमजोर करने का सबसे उपयुक्त समय हो सकता है। ट्रंप प्रशासन ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि स्थिति और बिगड़ी, तो सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा।

इस संभावित संघर्ष के बीच भू-राजनीतिक समीकरण भी तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के पड़ोसी और क्षेत्रीय शक्ति संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता का सम्मान करता है और किसी भी युद्ध का हिस्सा नहीं बनेगा। यूएई के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वह अपनी जमीन, हवाई क्षेत्र या समुद्री सीमा का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य हमले के लिए नहीं होने देगा। यह घोषणा अमेरिका के लिए एक बड़ा कूटनीतिक झटका मानी जा रही है, क्योंकि खाड़ी देशों के सहयोग के बिना बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यूएई ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी शत्रुतापूर्ण गतिविधि के लिए न तो आधार प्रदान करेगा और न ही कोई लॉजिस्टिक सहायता देगा।

दूसरी ओर, ईरान ने इन धमकियों का जवाब बेहद तल्ख लहजे में दिया है। तेहरान के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि उनकी सेना हाई अलर्ट पर है और किसी भी छोटे या सीमित हमले को पूर्ण युद्ध की घोषणा माना जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि यदि उसके परमाणु ठिकानों या सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, तो इसका जवाब इतना कठोर होगा कि पूरा क्षेत्र इसकी चपेट में आ जाएगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष भी इसी तरह के तनाव के दौरान अमेरिका ने अपने बी-2 बॉम्बर्स के जरिए कुछ खास ठिकानों को निशाना बनाया था। वर्तमान में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक बेड़े, जिसे आर्माडा कहा जा रहा है, की मौजूदगी ने यह संकेत दे दिए हैं कि आने वाले कुछ दिन वैश्विक शांति और तेल आपूर्ति की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होने वाले हैं।

चीन के परमाणु हथियार अब अमेरिका की मुट्ठी में? शी जनरल झांग का कच्चा चिट्ठा

बीजिंग (एजेंसी)। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के भीतर एक ऐसा भूचाल आया है जिसने बीजिंग की सत्ता के गलियारों को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सबसे वफादार माने जाने वाले और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन (सीएमसी) के उपाध्यक्ष, 75 वर्षीय जनरल झांग यूक्सिया के खिलाफ भ्रष्टाचार और जासूसी के बेहद गंभीर आरोपों के तहत जांच शुरू कर दी गई है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जनरल झांग पर चीन के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़ा अत्यंत गोपनीय कोर टेक्निकल डेटा अमेरिका को लीक करने का संदेह है। इसका मतलब है कि चीन के परमाणु हथियार अब अमेरिका की मुट्ठी में हो सकते? इस सनसनीखेज खुलासे के बाद न केवल चीन में बल्कि वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों के बीच भी हड़कंप मच गया है।

चीनी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इस कार्रवाई को अनुशासन और कानून का गंभीर उल्लंघन करार दिया है। सूत्रों के मुताबिक, चीनी सेना के भीतर हुई एक आंतरिक ब्रीफिंग में जनरल झांग पर कई संगीन आरोप मढ़े गए हैं। इनमें सबसे गंभीर आरोप परमाणु हथियारों की तकनीकी जानकारी साझा करना है, जो चीन की संप्रभुता और सैन्य शक्ति के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। इसके अतिरिक्त, झांग पर सेना में उच्च पदों पर पदोन्नति के बदले मोटी रिश्वत लेने, अपने पद का दुरुपयोग करने और सेना के भीतर अपना एक समानांतर राजनीतिक गुट बनाने के आरोप भी लगे हैं। यह मामला इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि झांग को राष्ट्रपति जिनपिंग का दाहिना हाथ माना जाता था और उनके खिलाफ कार्रवाई शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर बढ़ते अविश्वास को दर्शाती है।

जांच का दायरा केवल जनरल झांग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे सैन्य नेटवर्क पर देखा जा रहा है। जांच अधिकारियों ने उन सभी वरिष्ठ अफसरों के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर लिए हैं जिन्हें झांग के कार्यकाल के दौरान पदोन्नत किया गया था। यह कार्रवाई सेना के खरीद सिस्टम में फैले गहरे भ्रष्टाचार के नेटवर्क को उखाड़ फेंकने की कोशिश का हिस्सा मानी जा रही है। गौरतलब है कि 2023 से अब तक चीन ने 50 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और रक्षा उद्योग के प्रमुखों को उनके पदों से हटाया है, जिसमें पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू का नाम भी शामिल है। इस घटनाक्रम के बाद बीजिंग में तनाव का माहौल है और सोशल मीडिया पर तख्तापलट जैसी कई अपुष्ट अफवाहें तैर रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जनरल झांग की हिरासत के दौरान सुरक्षा बलों के बीच झड़पें भी हुई हैं, हालांकि इनकी कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि परमाणु डेटा लीक का आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित भी हो सकता है ताकि एक शक्तिशाली जनरल को पूरी तरह खत्म किया जा सके। वॉशिंगटन स्थित चीनी दूतावास ने इस मामले पर अधिक टिप्पणी न करते हुए इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति बताया है। फिलहाल, चीन ने परमाणु लीक के विशिष्ट आरोपों पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन इस कार्रवाई ने चीनी सेना की आंतरिक स्थिरता और उसके परमाणु सुरक्षा चक्र पर बड़े सवालिया निशान लगा दिए हैं।

खुलेआम हो रही हिंसा, अमेरिकी जनता से अनदेखा करने को कहा जा रहा

–मेयर जोहरान ममदानी ने फिर की आईसीई को पूरी तरह खत्म करने की मांग

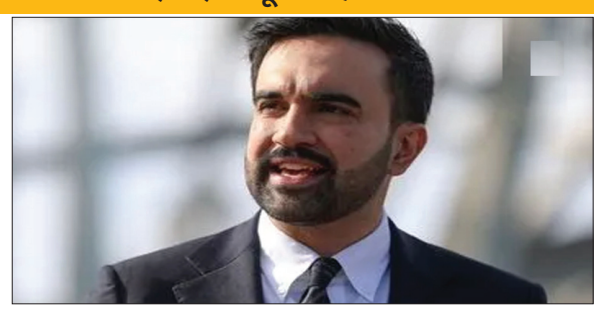

वाशिंगटन (एजेंसी)। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (आईसीई) को लेकर बहस और तेज हो गई है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने एक बार फिर आईसीई को पूरी तरह खत्म करने की मांग। उन्होंने आरोप लगाया कि यह एजेंसी खुलेआम हिंसा कर रही है, जिसे अमेरिकी जनता से अनदेखा करने को कहा जा रहा है। एक्स पर जारी बयान में ममदानी ने कहा कि आईसीई ने दिनदहाड़े रैनी गुड की हत्या की। तीन हफ्ते भी नहीं बीते थे कि एलेक्स प्रेट्टी को गोलियां मारी गईं। हर दिन हम देखते हैं कि लोगों को उनकी कारों, उनके घरों और उनकी जिंदगी से जबरन छीना जा रहा है। इस क्रूरता से नजरें नहीं फेर सकते। आईसीई को खत्म करो।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम में दिए इंटरव्यू में ममदानी ने मिनियापोलिस में हुई हालिया घटनाओं को भयावह बताया। उन्होंने नेताओं पर आरोप लगाया कि वे अमेरिकियों से उनकी आंखों और कानों पर भरोसा न करने को कह रहे हैं। ममदानी ने कहा कि रैनी गुड से जुड़ा वीडियो साफ है और उसे देखने के बाद किसी और नतीजे पर पहुंचना मुमकिन नहीं। रैनी गुड, 37 साल की अमेरिकी नागरिक थीं। जिन्हें 7 जनवरी को उनकी कार में बैठे हुए आईसीई एजेंट ने गोली मार दी थी।

अधिकारियों के मुताबिक वह किसी इमिग्रेशन रेड का लक्ष्य नहीं थीं। इस घटना के बाद मिनियापोलिस में कई हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन हुए। इसके कुछ ही समय बाद, 37 साल के एलेक्स प्रेट्टी की भी एक घटना में मौत हो गई, जहां कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंट ने उन पर कई गोलियां बरसाईं थी। जोहरान ममदानी का कहना है कि यह डर सिर्फ मिनियापोलिस तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क के लोग भी खुद को आतंकित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि वह न्यूयॉर्क सिटी में ऐसी कार्रवाइयों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे। बढ़ते विरोध और जांच के बीच ममदानी ने कहा कि अमेरिकी जनता सच सुनना और सच देखना चाहती है।

ड्रोन तकनीक को नई दिशा देगा चमगादड़ के उड़ान का तरीका

लंदन (एजेंसी)। वैज्ञानिकों के लिए लंबे समय से सवाल बना हुआ था कि पिच-ब्लैक अंधेरे में चमगादड़ इतनी सटीकता से रास्ता कैसे पहचान लेते हैं। घने जंगल, चारों तरफ घुप्प अंधेरा और तेज रफ्तार उड़ान, इसके बावजूद चमगादड़ कभी पेड़ों, पत्तियों या टहनियों से नहीं टकराते। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया है। यह खोज न केवल प्रकृति की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है, बल्कि भविष्य की ड्रोन और रोबोटिक तकनीक को भी नई दिशा दे सकती है। अब तक माना जाता था कि चमगादड़ पूरी तरह इको-लोकेशन यानी ध्वनि तरंगों के सहारे उड़ान भरते हैं और आसपास मौजूद हर चीज को सोनार की तरह मैप करते हैं। लेकिन नई स्टडी के मुताबिक, चमगादड़ सिर्फ आवाज़ की गूंज पर निर्भर नहीं रहते। वे ध्वनि के प्रवाह और उसकी गति को भी महसूस करते हैं, जिसे वैज्ञानिकों ने ÷अकूस्टिक फ्लो वेलोसिटी÷ नाम दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि चमगादड़ हर पत्ती या टहनी की अलग-अलग दूरी नहीं मापते, बल्कि ध्वनि के बहाव के पैटर्न से यह समझ लेते हैं कि सामने का वातावरण कितना घना है और किस रफ्तार से आगे बढ़ना सुरक्षित रहेगा।

इस सिद्धांत को साबित करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास प्रयोग किया, जिसे ÷बैट एक्सेलेरेटर मशीन÷ नाम दिया गया। यह करीब आठ मीटर लंबा एक उड़ान कॉरिडोर था, जिसमें लगभग 8,000 कृत्रिम पत्तियां लगाकर घने जंगल जैसा माहौल तैयार किया गया। इस प्रयोग में 100 से ज्यादा पिपिस्ट्रेल प्रजाति के चमगादड़ों की उड़ान को बारीकी से ट्रैक किया गया। वैज्ञानिकों ने इन नकली पत्तियों को आगे-पीछे खिसकाया, जिससे ध्वनि तरंगों के प्रवाह की गति बदलती रही। जब पत्तियां चमगादड़ों की ओर बढ़ाईं गईं और उन्हें ध्वनि का प्रवाह तेज महसूस हुआ, तो उन्होंने अपनी उड़ान की रफ्तार लगभग 28 प्रतिशत तक कम कर ली।

वहीं, जब पत्तियां पीछे हटाईं गईं और ध्वनि प्रवाह धीमा लगा, तो चमगादड़ों ने अपनी स्पीड बढ़ा दी। इससे यह साफ हुआ कि चमगादड़ वातावरण की गति को समझकर अपने उड़ान नियंत्रण को तुरंत बदल लेते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह प्रक्रिया डॉप्लर शिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है, वही सिद्धांत जिसकी वजह से एंबुलेंस के पास आने और दूर जाने पर सायरन की आवाज़ बदलती हुई महसूस होती है। यानी चमगादड़ सिर्फ ÷आवाज़ से देख÷ नहीं रहे होते, बल्कि वे आसपास की गति और बनावट को महसूस कर रहे होते हैं। इस खोज को ड्रोन और रोबोटिक्स की दुनिया में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

स्वामी,मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, एक घायल दूसरा पकड़ाया, गोकशी में हैं शामिल

बुलंदशहर (एजेंसी)। यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में लिया, जिनमें एक बदमाश घायल था। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना पहासू रोड पर झमका के पास उस समय हुई, जब थाना खुर्जा नगर की पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान दो संदिग्ध युवकों को रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की। इस मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि उसका साथी भाग गया। पुलिस ने अभियान चलाया और थोड़ी देर बाद दूसरे बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया। घायल बदमाश को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस पूछताछ में दोनों बदमाशों ने कबूल किया कि वे गोकशी की घटनाओं में शामिल हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दो दिन पहले खुर्जा नगर क्षेत्र में गौवंश के अवशेष मिलने की जो घटना सामने आई थी, उसे भी इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। इस मामले में पहले से ही थाना खुर्जा नगर में मुकदमा दर्ज है। खुर्जा सीओ ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात चेकिंग के दौरान यह मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने एक बदमाश का नाम नदीम और दूसरे का हुजैफा बताया है। पुलिस आगे जांच कर रही है।

देवी-देवताओं पर टिप्पणी को लेकर विवाद, दबंगों ने मां-बेटे का जुलूस निकाल पूरे गांव में घुमाया

हापुड़ (एजेंसी)। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में दबंगों ने मां बेटे का गांव में जुलूस निकालने का वीडियो वायरल हो गया है। जानकारी के मुताबिक अनुसूचित जाति का युवक देवी-देवताओं पर टिप्पणी कर रहा था। इसी बात से नाराज जाट समाज के युवकों ने राम मंदिर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तीसरी वर्षगांठ पर गांव के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में अनुसूचित जाति को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। इस बात से नाराज अनुसूचित जाति के लोगों ने मां-बेटे को पंचायत में बुलाया और वहां से पूरे गांव में हाथ जोड़कर जुलूस के रूप में घुमाया। दबंग लोगों का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस मामले में कुछ लोग दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्रवाई को लेकर गांव में एकत्र हो गए। वहीं, पुलिस ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है।

गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन, मदनी ने फैसले को अंसवैधानिक बताया

सहारनपुर (एजेंसी)। उत्तराखंड में गंगोत्री धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में भी इस दिशा में कदम उठाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इस पूरे मामले पर जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस फैसले को अंसवैधानिक करार दिया है। मदनी ने कहा कि उन्हें लगता है कि देश उनका है और वे जनता को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं, लेकिन समय बदल गया है। यह अच्छी बात है कि लोग प्यार और भाईचारे से रहें और जमीयत उलेमा-ए-हिंद यही सिखाता है। यह सिर्फ केदारनाथ में नहीं है। असम में पूरी कॉलोनियों को तोड़ा जा रहा है और लाखों मुसलमानों को बांग्लादेशी बताया जा रहा है। सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी इस मुद्दे पर सरकार का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि इन?होंने अजीब स्थिति बना दी है। अगर आप देश के नागरिक हैं तो अपनी नागरिकता साबित करें। क्या सरकार कुछ साबित नहीं करेगी। अब इन्होंने हिंदुओं पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूछ रहे हैं कि वे हिंदू हैं या नहीं। कोई कैसे साबित करेगा कि वह हिंदू है या नहीं।

घरेलू नौकरानी का रेप करने के आरोप में अभिनेता गिरफ्तार

मुंबई (एजेंसी)। एक अभिनेता द्वारा शादी का वादा करके 10 साल तक अपनी घरेलू नौकरानी का रेप करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि 41 साल की एक महिला की शिकायत के आधार पर, हाल ही में ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर में दिखे नदीम खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वह फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। शिकायत के अनुसार, महिला ने अलग-अलग अभिनेताओं के यहां घरेलू नौकरानी के तौर पर काम किया था और सालों पहले खान के संपर्क में आई थी, और वे करीब आ गए थे। महिला ने आरोप लगाया कि खान ने उससे शादी करने का वादा किया था, और उसी भरोसे पर, उसने 10 साल की अवधि में मलाड के मालवणी में उसके घर और पश्चिमी उपनगरों में वर्सोवा में अपने घर पर कई बार उसका रेप किया। हालांकि, बाद में उसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया जिसके बाद महिला ने वर्सोवा पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। बहरहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है।

कोलकाता के दो गोदामों में भीषण आग, 8 लोग जिंदा जले, आग बुझाने में लगे 7 घंटे

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में सोमवार को दो गोदामों में भीषण आग में कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई। यह हादसा कोलकाता के नजीराबाद इलाके में हुआ। पुलिस के मुताबिक नजीराबाद में स्थित दो गोदाम, जो एक-दूसरे के बिल्कुल पास में ही थे, अचानक आग की लपटों में घिर गए। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए सात घंटे लगे। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान करीब पांच बजे घटनास्थल से तीन शव बरामद किए गए और बाद में पांच अन्य शवों को ढूंढ निकाला गया। बारुईपुर जिले के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव बुरी तरह झुलसने के कारण अभी मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। उन्होंने कहा कि मलबा पूरी तरह से साफ होने के बाद ही पता चल पाएगा कि घटना स्थल पर कोई और शव तो नहीं है या मलबे में कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है। पुलिस ने बताया कि शुरुआत में छह लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी लेकिन फंसे हुए लोगों के परिवारों के मुताबिक यह संख्या 10 से ज्यादा हो सकती है क्योंकि पास के गोदामों में साज सज्जा का काम करने वाली एक कंपनी और मोमो बेचने वाली एक कंपनी के मजदूर काम करते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि बचाव अभियान जारी है। बोस ने दो इकाइयों के प्रबंधन द्वारा अपनाए जा रहे अग्नि सुरक्षा नियमों के बारे में कहा कि वर्ष में दो बार अग्नि सुरक्षा ऑडिट किया जाता है और हर खामी को दूर किया जाता है, फिर भी मालिकों व कंपनी के अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण रूप से पालन करें। जैसे ही शाम ढलने लगी, मृतकों और लापता व्यक्तियों के कई रिश्तेदार घटनास्थल पर जमा हो गए और अग्निशमन सेवा एवं पुलिस अधिकारियों से स्थिति की जानकारी लेने लगे।

बैंगलुरु में कांग्रेस का 'लोक भवन चलो' मार्च,

सीएम सिद्धारमैया गरजे- संवैधानिक अधिकार छीन रही केंद्र सरकार

बैंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस का विरोध वीबी जी राम जी विधेयक के माध्यम से एमजीएनआरईजीए को निरस्त करने के विरोध में था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और केंद्र सरकार के हाथों में सत्ता का केंद्रीकरण करता है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) ने आज बेंगलुरु में केंद्र के वीबी जी राम जी अधिनियम के खिलाफ राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने %लोक भवन चलो% विरोध प्रदर्शन के लिए बसों से कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए लोक भवन तक का सफर तय किया।

सिद्धारमैया ने कहा कि पार्टी ने मांग की है कि इस कानून को रद्द किया जाए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को बहाल किया जाए। राजभवन में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में राज्य भर से हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अदालत के आदेश का पालन करते हुए रैली नहीं निकाली और इसके बजाय बसों से राजभवन पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज, केपीसीसी की ओर से, हमने राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस प्रदर्शन में हजारों लोगों ने भाग लिया। चूंकि अदालत का आदेश है, इसलिए हमने विरोध रैली नहीं निकाली और दो बसों से राजभवन आए।

सिद्धारमैया ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन वीबी जी राम जी विधेयक के माध्यम से एमजीएनआरईजीए को निरस्त करने के विरोध में किया जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कदम संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है और सत्ता को केंद्र सरकार के हाथों में केंद्रित करता है। उन्होंने कहा कि कारण यह है कि वीबी जी राम जी विधेयक के जरिए एमजीएनआरईजीए को निरस्त कर दिया गया है। वे संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीन रहे हैं। अब, इस वीबी जी राम जी विधेयक के साथ, केंद्र सरकार ही सब कुछ तय करेगी।

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि कांग्रेस आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक में अपना आंदोलन तेज करेगी। उन्होंने कहा, ÷हम पूरे राज्य में अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्हें इस वीबी जी राम जी विधेयक को निरस्त करके एमजीएनआरईजीए को वापस लाना चाहिए। तब तक, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे।÷ उन्होंने आगे कहा कि पार्टी जन समर्थन जुटाने के लिए राज्य के कई हिस्सों में पदयात्रा करेगी। उन्होंने कहा कि हम राज्य के कई स्थानों पर पदयात्रा करेंगे। इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि कर्नाटक की सभी ग्राम पंचायतों का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा जाएगा।

झारखंड नगर निकाय चुनाव : मतदान 23 फरवरी को, 27 को आएंगे परिणाम

-चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू

रांची(एजेंसी)। झारखंड में लंबे समय से प्रतीक्षित नगर निकाय चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने रांची में कहा कि राज्य की सभी नगर पालिकाओं, नगर निगमों और नगर परिषदों के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही पूरे झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 27 फरवरी को आएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव, 9 जनवरी को जारी की गई आरक्षण सूची के आधार पर ही होंगे। इस बार रांची नगर निगम का मेयर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वहीं, धनबाद और चास नगर निगम के मेयर पद को सामान्य श्रेणी के लिए रखा गया है। इसके साथ ही राज्य की 20 नगर परिषदों में अध्यक्ष पदों के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और अनारक्षित श्रेणियों के साथ-साथ महिला आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, जामताड़ा, साहेबगंज और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिलों की कई नगर पंचायतों में अध्यक्ष का पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया है। वहीं, खूंटी, लातेहार, गोड्डा और रांची जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग को प्राथमिकता दी गई है।

हिमाचल में जमकर हुई बर्फबारी, मनाली में सैकड़ों पर्यटक फंसे, रास्तों पर लग गया लंबा जाम

मनाली(एजेंसी)। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में 23 जनवरी से जारी भारी बर्फबारी ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। मनाली और इसके आसपास के क्षेत्रों में कुदरत के सफेद कहर की वजह से सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे सैकड़ों पर्यटक बीच रास्ते में फंस गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह मनाली के सोलंगनाला में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है।

सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर के कारण नेशनल हाईवे-3 पर यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि, अधिकारियों ने सोमवार को सोलंगनाला तक सड़क साफ करने का काम किया, लेकिन वर्तमान में वहां केवल छोटे और हल्के वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति दी गई है। बसों का संचालन अभी भी बाधित है और वे मनाली से करीब 16 किलोमीटर दूर पतलीकुहल तक ही जा पा रही हैं। रविवार की तुलना में स्थिति में मामूली सुधार जरूर हुआ है, लेकिन पर्यटकों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पिछले दिनों मनाली में 15 किलोमीटर लंबा भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जहां पर्यटकों को कड़कड़ाती ठंड में अपना सामान उठाकर पैदल चलते हुए देखा गया।

जिला प्रशासन लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मुख्य सड़कें बंद होने के कारण पर्यटक अपने होटलों तक ही सीमित हैं। सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्धस्तर पर जारी है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह बहाल करने में अभी कुछ समय और लग सकता है। फिसलन भरी सड़कों को देखते हुए पतलीकुहल से मनाली की ओर केवल चार पहिया वाहनों को ही जाने दिया जा रहा है। मौसम विभाग ने 27 जनवरी के लिए भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिससे पतलीकुहल-मनाली और मणिकरण-भुंतर मार्ग के पूरी तरह बंद होने का खतरा बढ़ गया है। पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विशेष एडवाइजरी जारी की है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम साफ होने तक ऊंचे इलाकों, नदियों, नालों और हिमस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों की ओर न जाएं। कुल्लू पुलिस के अनुसार, यदि मौसम और बिगड़ता है तो केवल 4गुणा4 वाहनों को ही आगे बढ़ने की अनुमति होगी। यात्रियों को वैकल्पिक मार्गों, जैसे राइट बैंक मार्ग, का उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। खराब मौसम और तूफान की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सभी से सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया है।

2000 के नोटों से भरे दो ट्रक की लूट ने लिया सियासी रंग, कांग्रेस-बीजेपी आमने-सामने

-प्रियांक खड़गे ने नकदी की इस आवाजाही को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से जोड़ा

बेंगलुरु, (एजेंसी)। कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा पर 2000 के नोटों के 400 करोड़ रुपए की लूट ने सियासी रंग ले लिया है। कर्नाटक की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी ने एक-दूसरे पर जमकर निशाना साधा। पिछले साल 22 अक्टूबर को चोरला घाट पर हुई इस लूट का मामला कुछ समय पहले तब सामने आया था, जब पीड़ित संदीप पाटिल ने नासिक में लूट की शिकायत दर्ज कराई।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित संदीप ने बताया कि दो ट्रक में भरकर यह पैसा ले जाया जा रहा था। उसी वक्त 6 लोगों ने हथियारों के दम पर उसे लूट लिया। घटना की जानकारी सामने आते ही कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाते हुए नकदी की इस आवाजाही को गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि यह पैसा किसका था। जांच होने दीजिए ताकि पता चल सके कि यह कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी या शिवसेना का है या नहीं। असल सवाल तो यह है कि बीजेपी सरकारें क्या कर रही हैं। ये तीनों सरकारें अपनी नाक के नीचे ये सारी गतिविधियां कैसे कर रही हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बीजेपी विधायकों के इस आरोप का जिक्र करते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद 2,000 रुपए के नोटों को काले धन से सफेद धन में बदलने के लिए तिरुपति ले जाया जा रहा था, प्रियांक खड़गे ने पूछा कि उनके पास ऐसी जानकारी कैसे है, जो सरकारों के पास भी नहीं है? उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश, जहां तिरुपति स्थित है, पर किसका शासन है? केंद्र को इन सवालों का जवाब देना होगा। प्रियांक ने कहा कि पीएम के पास जेन जेड और भजन क्लबों के बारे में बोलने का समय है, लेकिन उन्हें ट्रकों में तस्करी किए जा रहे 400 करोड़ रुपए की नकदी की कोई जानकारी नहीं है। क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सो रहे हैं? 'वह कहां है?'

प्रियांक खड़गे द्वारा उठाए सवालों के बाद बीजेपी नेता चलावादी नारायणस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर फंडिंग का स्त्रोत बनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक से पैसा सभी चुनावों के लिए भेजती है, क्योंकि कांग्रेस-शासित तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश से फंड नहीं जुटाया जा सकता।

उन्होंने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गृह लक्ष्मी गारंटी योजना के तहत फरवरी और मार्च 2025 के लिए 5,000 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। पहले कहा गया कि भुगतान हो चुका है, बाद में उन्होंने खुद माना कि भुगतान नहीं हुआ। ऐसा सिर्फ कांग्रेस ही कर रही है। वहीं, बेलगावी के पुलिस अधिकारी ने इस मामले पर कहा कि अब तक कर्नाटक में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, क्योंकि न तो कोई शिकायत और न ही कोई ठोस सबूत सामने आए हैं। सिर्फ अफवाहों के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। बता दें नासिक पुलिस के मुताबिक घटना में 2000 रुपए के पुराने नोटों में 400 करोड़ रुपए मौजूद थे, जिन्हें दो ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा था। इन्हें रास्ते में लूट लिया गया। महाराष्ट्र पुलिस ने इस मामले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है और रुपयों की दावे की जांच के लिए विशेष समिति गठित की है।

शंकराचार्य विवाद में उमा भारती की एंट्री, बोलीं- सबूत मांगना गलत, मेरा बयान योगी के खिलाफ नहीं

नई दिल्ली (एजेंसी)। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की नेता उमा भारती ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से उनके शंकराचार्य पदवी का प्रमाण मांगना मर्यादा का उल्लंघन है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके इस कथन का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अनादर करना नहीं है। एक पोस्ट में भारती ने कहा कि इस तरह के प्रमाण मांगने का अधिकार केवल शंकराचार्य या विद्वान परिषद के पास है। उमा भारती ने एक्स पर लिखा कि मुझे विश्वास है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज एवं उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कोई सकारात्मक समाधान निकल आएगा किंतु प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा शंकराचार्य होने का सबूत मांगना, यह प्रशासन ने अपनी मर्यादाओं एवं अधिकारों का उल्लंघन किया है, यह अधिकार तो सिर्फ शंकराचार्यों का एवं विद्वत परिषद का है। हालांकि, इसके बाद उमा भारती ने एक और एक्स पोस्ट किया।

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण 2029 का लोकसभा चुनाव अयोध्या से लड़ेंगे?

-फैजाबाद से विनय कटियार ने टिकट मांगा, बृजभूषण बोले- वह इसके हकदार

नई दिल्ली(एजेंसी)। पूर्व बीजेपी सांसद बृज भूषण शरण सिंह ने फैजाबाद से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने का संकेत दिया है और कहा कि सही वक्त पर आखिरी फैसला लिया जाएगा। बृजभूषण ने एक शोरूम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से यह बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या जिले की एकमात्र लोकसभा सीट फैजाबाद से पूर्व बीजेपी सांसद विनय कटियार पार्टी टिकट के हकदार हैं।

बृज भूषण ने कहा कि यहां से दावा करना कटियार का अधिकार है और इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। वह इसके पूरी तरह हकदार हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद फैजाबाद से अप्रत्याशित विजेता थे। उन्होंने बीजेपी के लल्लू सिंह को हराया था। हाल ही में अपने जन्मदिन के मौके पर आयोजित शक्ति प्रदर्शन में बृज भूषण ने 2029 के आम चुनावों की तैयारी का संकेत दिया था।

उनके के बेटे और कैसरगंज से मौजूदा बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि पिता-पुत्र की जोड़ी 2029 के चुनावों में मैदान में उतरेगी। सोमवार को बृज भूषण सिंह ने युवाओं और सोशल मीडिया से मिल रहे समर्थन के लिए आभार जताया और अपने बढ़ते प्रभाव का श्रेय जनता के प्यार और यकीन को दिया, जिसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत बताया।

भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने यूपी में तीन संसदीय क्षेत्रों का छह बार प्रतिनिधित्व किया है। पिछले दिनों उन पर कई महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद 2024 के आम चुनावों से पहले बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था। देश के कुछ टॉप पहलवानों, ओलंपियन विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन किया और बृज भूषण पर अनुचित व्यवहार और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। पिछले साल दिल्ली कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण को बरी कर दिया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें बृजभूषण के खिलाफ मामला रद्द करने की सिफारिश की गई थी।

आदिवासी बस्तियों को उजाड़ने के विरोध में एकनाथ शिंदे के घर के बाहर रातभर प्रदर्शन

-बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के घरों को उजाड़ना, मानवाधिकार का उल्लंघन

मुंबइ (एजेंसी)। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के वन क्षेत्रों में सालों से रह रहे आदिवासियों और प्रशासन के बीच तनाव बढ़ गया है। सोमवार को प्रशासन द्वारा आदिवासियों की बस्तियों को तोड़ने के विरोध में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित घर के बाहर रातभर प्रदर्शन किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वे पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं। उन्होंने सोमवार को प्रशासन द्वारा उनके आवासों पर की गई तोड़फोड़ की कार्रवाई की निंदा की और देर रात डिप्टी सीएम शिंदे के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। राज्य आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जब तक 2018 की पुनर्वास योजना लागू नहीं हो जाती और प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया नहीं जाता, तब तक तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले संगठन के एक पदाधिकारी के मुताबिक पुनर्वास योजना पर चर्चा का आश्वासन मिलने के बाद आदिवासियों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने वाली आदिवासी बस्तियों पर सोमवार को प्रशासन ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। कार्रवाई से नाराज आदिवासियों का कहना है कि वे इन जंगलों में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और उनके पास यहां रहने का अधिकार है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उनके घरों को उजाड़ना उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है। राज्य आदिवासी विकास समिति के अध्यक्ष और पूर्व विधायक ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर कड़े सवाल उठाए हैं।

गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल और खरगे को तीसरी पंक्ति में बिठाया, छिड़ गई सियासी जंग

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश की एकता, गरिमा और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक माना जाने वाला गणतंत्र दिवस इस बार राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन गया। कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रपति भवन तक, राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के सम्मान व प्रोटोकॉल को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी महाभारत छिड़ी कि उत्सव का माहौल सियासी कुरुक्षेत्र में तब्दील होता नजर आया।

विवाद की शुरुआत कर्तव्य पथ पर आयोजित मुख्य परेड के दौरान हुई। यहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को तीसरी पंक्ति में बिठाया गया, जिस पर कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई। पार्टी ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन और विपक्ष के शीर्ष नेताओं का जानबूझकर किया गया अपमान करार दिया। कांग्रेस नेतृत्व ने सवाल उठाया कि क्या नेता प्रतिपक्ष के साथ ऐसा व्यवहार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और परंपराओं के अनुरूप है? विपक्ष ने 2014 की पुरानी तस्वीरें साझा कर केंद्र सरकार को घेरा, जिसमें तत्कालीन विपक्षी नेता अग्रिम पंक्तियों में नजर आ रहे थे। कांग्रेस का आरोप है कि यह सरकार की हीन भावना को दर्शाता है। हालांकि, सत्ता पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि बैठने की व्यवस्था राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा जारी टेबल ऑफ प्रेसीडेंस के नियमों के तहत ही की गई थी, जिसमें विभिन्न पदों के लिए वरीयता क्रम निर्धारित होता है।

गणतंत्र दिवस की शाम राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के दौरान विवाद और गहरा गया। इस बार कार्यक्रम की थीम पूर्वोत्तर भारत (नॉर्थ ईस्ट) पर आधारित थी। समारोह में प्रधानमंत्री और विदेशी मेहमानों सहित सभी को पारंपरिक पटका दिया गया था। विवाद तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी उस पटके को गले में पहनने के बजाय हाथ में पकड़े नजर आए। बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी को घेरते हुए इसे पूर्वोत्तर की संस्कृति और राष्ट्रपति पद का अपमान बताया। सत्ता पक्ष के नेताओं का दावा है कि राष्ट्रपति द्वारा आग्रह किए जाने के बावजूद उन्होंने पटका नहीं पहना। बीजेपी का आरोप है कि विपक्ष की यह उपेक्षा भारत की सांस्कृतिक विविधता के प्रति उनके नजरिए को दर्शाती है। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे फर्जी प्रोपेगेंडा करार दिया। पार्टी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी का पूर्वोत्तर के प्रति प्रेम और जुड़ाव जगजाहिर है। कांग्रेस सांसदों ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी फुटेज देखने पर सच्चाई साफ हो जाएगी कि राहुल गांधी ने पटका पहना था। कुल मिलाकर, इस साल का गणतंत्र दिवस समारोह केवल सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक झांकियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सत्ता और विपक्ष के बीच बढ़ती कड़वाहट का गवाह भी बना। जहां कांग्रेस इसे आत्मसम्मान और लोकतांत्रिक परंपराओं का हनन बता रही है, वहीं बीजेपी इसे विपक्ष की नकारात्मक राजनीति करार दे रही है। राष्ट्रीय पर्व के इस मौके पर उभरे विवादों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में यह सियासी तल्खी और बढ़ सकती है।